epaper.dehatsandesh.com

3 रावी के तेज बहाव से जमीन का कटाव जोरो पर

5 रोहित और विराट के 2027 विश्व कप में खेलने पर बोले आकाश चोपड़ा, यह भी बहुत दूर की बात है लेकिन..

8 डीजीबीआर ने जम्मू संभाग में सड़क बुनियादी ढांचे का निरीक्षण किया

मौसम जम्मू — न्यूनतम 19 — अधिकतम 23

E-mail: dehatsandesh@gmail.com

जम्मू-कश्मीर का एकमात्र ग्रामीण दैनिक

देहात संदेश

वर्ष 22, जम्मू तवी, अंक 219 | जम्मू तवी, शुक्रवार 05 सितम्बर 2025 | मूल्य- 3 रूपये (लेह) 4 रूपये | पृष्ठ -8

परिषद ने 22 सितंबर से प्रभावी जीएसटी को 5% और 18% के स्लैब में सरल बनाया

नई दिल्ली, 4 सितम्बर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में और राज्यों के वित्त मंत्रियों की उपस्थिति में, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 56वीं बैठक बुधवार को जीएसटी व्यवस्था को सरल बनाने और उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से लिए गए ऐतिहासिक निर्णयों के साथ संपन्न हुई।

परिषद ने लंबे समय से प्रतीक्षित 5% और 18% के सरलीकृत दो-स्लैब वाले जीएसटी ढांचे को मंजूरी दे दी, जो वर्तमान चार-स्तरीय प्रणाली 5%, 12%, 18% और 28% के स्थान पर लागू होगा। तंबाकू, लक्जरी कारों, ऑनलाइन गेमिंग और चीनी-मीठे पेय पदार्थों जैसी हानिकारक वस्तुओं के लिए भी एक विशेष 40% स्लैब पेश किया गया है। नया ढांचा 22 सितंबर 2025 से प्रभावी होगा। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि इस पुनर्गठन का उद्देश्य आवश्यक वस्तुओं पर करों में कटौती करके और कई क्षेत्रों में व्याप्त विकृतियों को दूर करके आम आदमी और मध्यम वर्ग को राहत पहुँचाना है। बैठक के बाद उन्होंने कहा, आम आदमी और मध्यम वर्ग की वस्तुओं के लिए, करों में पूरी तरह से कटौती की गई है। उन्होंने आगे कहा कि ये बदलाव सरकार के सामर्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने को दर्शाते हैं।

रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ें सस्ती होंगी

कई आम उपभोग वाली वस्तुओं पर कर में भारी कटौती होगी। हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप, शैंपू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबलवेयर और किचनवेयर जैसी वस्तुओं को उच्च कर स्लैब से 5% के स्लैब में स्थानांतरित कर दिया गया है।

खाद्य मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय राहत देते हुए, नमकीन, सॉस, पास्ता, नूडल्स, चॉकलेट, कॉफ़ी, मक्खन, घी, संरक्षित मांस, कॉर्नफ्लेक्स और स्नैक्स जैसी आवश्यक वस्तुओं पर कर की दर 5त्न कर दी गई है।

अति-उच्च तापमान दूध, पनीर, छेना और सभी भारतीय रोटियाँ (रोटी, पराठा, आदि) सहित दैनिक उपयोग की वस्तुएँ अब कर-मुक्त होंगी।

उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं पर राहत

एक बड़े बदलाव के तहत, एयर कंडीशनर, डिशवॉशर, सभी आकार के टेलीविजन सेट और 350 सीसी तक के इंजन वाली मोटरसाइकिलों पर अब 28% के बजाय 18% जीएसटी लगेगा। विश्लेषकों का अनुमान है कि इन उत्पादों की कीमतों में 8त्न से

10% की गिरावट आएगी, जिससे आगामी त्योहारी सीज़न में मांग बढ़ेगी।

वित्त मंत्री ने कृषि और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों पर कर में कटौती की भी घोषणा की। उन्होंने कहा, ट्रैक्टर, थ्रेशर, बेलर और खाद बनाने वाले उपकरण जैसी कृषि मशीनों पर कर 12त्न से घटकर 5त्न हो रहा है। इसी तरह, पवन टरबाइन, बायोगैस संयंत्र और सौर पैनल जैसे नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण भी 5त्न के स्लैब में आ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक स्वास्थ्य क्षेत्र में है।

कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और पुरानी बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 33 जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी शून्य कर दिया गया है। कई अन्य दवाओं पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। चश्मा और दृष्टि-सुधारक चश्मों पर अब 28% से घटकर केवल 5% जीएसटी लगेगा। बीमा के मामले में, सीतारमण ने सभी व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर पूर्ण जीएसटी छूट की घोषणा की, जिनमें टर्म लाइफ, यूलिप, एंडोमेंट प्लान, फैमिली फ्लोटर और वरिष्ठ नागरिक पॉलिसियाँ शामिल हैं। स्क्वायर इंश्योरेंस के सीईओ आकाश परवाल ने कहा, स्वास्थ्य और जीवन बीमा से जीएसटी हटाने से प्रीमियम सीधे तौर पर कम हो जाएगा, जिससे बीमा अधिक किफायती और सुलभ हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा,

प्रधानमंत्री ने फैसले की सराहना की

प्रधानमंत्री मोदी ने इस फैसले की सराहना करते हुए ङ्क पर लिखा कि इन सुधारों से आम आदमी, किसानों, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं को लाभ होगा , साथ ही जीएसटी को सरल बनाया जाएगा और व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित की जाएगी।

वर्तमान में, 18% जीएसटी 25,000 की स्वास्थ्य पॉलिसी पर लगभग 4,500 का अतिरिक्त बोझ डालता है, जिससे कई मध्यम वर्गीय परिवार हतोत्साहित होते हैं। यह सुधार बीमा की पहुँच को काफ़ी बढ़ा सकता है।

ऑटोमोबाइल- छोटी कारों को राहत, हाइब्रिड और लग्ज़री वाहनों पर ज़्यादा टैक्स

सबसे ज़्यादा कर कटौती छोटी कारों पर हुई है, जो भारत के यात्री वाहन बाज़ार की रीढ़ हैं। 1200ष्क तक के इंजन वाली पेट्रोल, CNG और LPG कारों और चार मीटर लंबाई वाली 1500CC तक की डीज़ल कारों पर अब 28त्न की बजाय 18% GST लगेगा। इस कटौती से मारुति स्विफ्ट, हुंडई i10, टाटा पंच जैसे लोकप्रिय मॉडलों और ब्रेज़ा व वेन्यू जैसी कॉम्पैक्ट SUV की एक्स-शोरूम कीमतों में 5% से 7%की कमी आने की उम्मीद है। हालांकि, सरकार ने हाइब्रिड और बड़े वाहनों के लिए एक सख्त नियम लागू किया है। 1200 (पेट्रोल) या 1500CC (डीज़ल) से ज़्यादा इंजन वाली या चार मीटर से ज़्यादा लंबाई वाली कारें और 350CC से ज़्यादा क्षमता वाली मोटरसाइकिलें नए 40% स्लैब में आ जाएँगी। इसका मतलब है कि टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस हाइब्रिड और होंडा सिटी ई:एचईवी जैसे मॉडल और महंगे हो जाएँगे, जिससे उन वाहन निर्माताओं को निराशा होगी जिन्हें उम्मीद थी कि हाइब्रिड वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक सेतु के रूप में कर प्रोत्साहन मिलेगा। शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर केवल 5त्न जीएसटी लागू रहेगा, जो सीधे ईवी अपनाने की दिशा में एक स्पष्ट नीतिगत कदम का संकेत देता है। ट्रैक्टर, कृषि मशीनरी, थ्रेशर, कम्पोस्टिंग मशीन, जैव-कीटनाशक और प्राकृतिक मेन्थॉल पर कर में कटौती से कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ होगा, सभी पर कर 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर व बडगाम के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया

श्रीनगर 04 सितम्बर। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर और बडगाम ज़िलों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का व्यापक दौरा किया। उन्होंने लस्जन के पास शलिना में झेलम नदी के तटबंध टूटने के बाद की स्थिति का जायज़ा लेने के लिए कई आंतरिक जलमग्न इलाकों तक नाव से पहुंचकर निरीक्षण किया।

मुख्यमंत्री ने टैंगन लस्जन और शलिना क्षेत्रों का दौरा किया, जहाँ उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से हालात का आकलन किया। बाढ़ का सामना करते हुए वे नाव के माध्यम से जलमग्न क्षेत्रों में पहुँचे और प्रभावित नागरिकों से भेंट की। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार हरसंभव मदद और सहयोग प्रदान करेगी।

उन्होंने कहा प्रशासन की तात्कालिक प्राथमिकता प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित निकालना, उन्हें सुरक्षित ठिकानों तक पहुँचाना और तुरंत राहत पहुँचाना है।

उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिया कि जलभराव वाले क्षेत्रों से परिवारों को सुरक्षित और सुगम निकासी सुनिश्चित की जाए तथा अस्थायी शिविर स्थापित किए जाएँ, जिनमें सुरक्षित पेयजल, भोजन और स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ।

दौरे के दौरान मुख्यमंत्री के साथ उपमुख्यमंत्री श्री सुरिंदर कुमार चौधरी, मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री नासिर असलम वानी तथा चाडूरा, चैनापोरा और लाल चौक निर्वाचन क्षेत्रों के विधायक भी मौजूद थे। अतिरिक्त मुख्य सचिव जल शक्ति विभाग श्री शलीन काबरा, संभागीय आयुक्त कश्मीर, श्रीनगर नगर निगम आयुक्त, श्रीनगर व बडगाम के उपायुक्त, निदेशक स्वास्थ्य सेवाएँ कश्मीर, मुख्य अभियंता सिंचाई

व बाढ़ नियंत्रण कश्मीर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उनके साथ थे। मुख्यमंत्री ने आसपास के निवासियों से प्रशासन द्वारा जारी सलाहों का कड़ाई से पालन करने और राहत एवं बचाव कार्यों में लगे अधिकारियों को पूरा सहयोग देने का आग्रह किया। स्थल पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा लगातार बारिश और झेलम नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण, कल से हमें जो आशंका थी, वह दुर्भाग्यवश सही साबित हुई, जिसके चलते कई क्षेत्रों में बाढ़ आ गई। सबसे पहले, हमें अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि समय पर निकासी हुई और सबसे अहम बात यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई। उन्होंने स्वीकार किया कि बाढ़ से काफ़ी वित्तीय और संपत्तिगत नुकसान हुआ है। इसे नकारा नहीं जा सकता। हमें इस बारे में उचित निर्णय लेने होंगे। केंद्र सरकार की एक टीम पहले ही जम्मू के दस ज़िलों में हुए नुकसान का आकलन कर रही है। मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह से आग्रह करूंगा कि वही टीम कश्मीर भी भेजी जाए ताकि कुलगाम, अनंतनाग, श्रीनगर, बडगाम, गांदरबल, बारामुला, बांदीपोरा और अन्य प्रभावित क्षेत्रों का नुकसान सही तरीके से आंका जा सके। उन्होंने कहा हमारी जिम्मेदारी है कि हर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के नुकसान का जायज़ा लिया जाए और राहत व पुनर्वास के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएँ। मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों को पेयजल उपलब्ध कराने तथा नावों की संख्या बढ़ाकर जलमग्न पशुशालाओं में फँसे पशुओं को बाहर निकालने के भी निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने जम्मू-कश्मीर के विभिन्न संभागों में बाढ़ पश्चात पुनर्स्थापना का आकलन किया

जम्मू, 04 सितम्बर। मुख्य सचिव अतल डुल्लू ने प्रशासनिक सचिवों, संभागीय आयुक्तों तथा जिला उपायुक्तों की उपस्थिति में दो अलग-अलग बैठकें आयोजित कीं। इन बैठकों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति और चल रही पुनर्स्थापना कार्यवाइयों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठकों में मुख्य सचिव ने सड़कों, पुलों, विद्यालयों और अन्य आवश्यक ढाँचों सहित सार्वजनिक अवसंरचना को हुए नुकसान का विस्तृत मूल्यांकन लिया। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में बिजली, पेयजल और स्वच्छता सेवाओं जैसी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता की समीक्षा भी की। स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया गया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में संभावित स्वास्थ्य खतरों पर जागरूकता अभियानों को तीव्र किया जाए और जनकल्याण हेतु विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएं। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि प्रभावित स्कूलों का व्यापक सुरक्षा ऑडिट किया जाए और अकादमिक गतिविधियों के दोबारा शुरू

होने से पहले उचित स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त, मुख्य सचिव ने खाद्यान्न, ईंधन और पेट्रोलियम उत्पादों जैसी आवश्यक वस्तुओं का स्टॉक, तथा क्षतिग्रस्त सड़कों पर चल रहे पुनर्स्थापना कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की।

जीएसटी सुधारों से जम्मू-कश्मीर के राजस्व में 10-12% की कमी आ सकती है- उमर

श्रीनगर, 4 सितंबर । जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को चेतावनी दी कि प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर सुधारों से केंद्र शासित प्रदेश के राजस्व में 10-12 प्रतिशत की कमी आ सकती है, जिससे पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद सार्वजनिक राजस्व में आई गिरावट के कारण पहले से ही कमज़ोर वित्तीय स्थिति और भी बदतर हो जाएगी।

56वीं जीएसटी परिषद की बैठक में प्रसारित अपने लिखित

भाषण में, अब्दुल्ला ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की वित्तीय स्थिरता की रक्षा के लिए सुरक्षा उपाय बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा, फ्अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र, जैसे पर्यटन, परिवहन, निर्माण, ऑटोमोबाइल, अप्रैल 2025 के बाद ठप हो गए हैं। प्रस्तावित सुधार हमारे जीएसटी राजस्व में 10-12 प्रतिशत की और कमी ला सकते हैं। इसलिए, जम्मू-कश्मीर के वित्त मंत्री के रूप में, मेरा मानना ??है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की वित्तीय स्थिरता के लिए उपयुक्त तंत्र और सुरक्षा उपाय स्थापित करना महत्वपूर्ण है।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने बुधवार को 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की सरलीकृत दो-स्लैब संरचना को मंजूरी दे दी, जो 22 सितंबर से लागू होगी। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि यह निर्णय सभी राज्यों की सहमति से लिया गया है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक बुधवार को शुरू हुई और गुरुवार को समाप्त होगी। स्लैब को युक्तिसंगत बनाने का कदम अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के तहत सबसे प्रतीक्षित सुधारों में से एक रहा है।

हर पात्र को दिलाएं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ : मुख्यमंत्री

गोरखपुर, 4 सितंबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि हर पात्र व्यक्ति को शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित किया जाए। जरूरतमंदों के इलाज से लेकर आवास तक की व्यवस्था के लिए सरकार की योजनाओं का लाभ बड़े पैमाने पर दिया जा रहा है। पर, किन्हीं कारणों से यदि कोई व्यक्ति इन योजनाओं के दायरे में अभी नहीं आ पाया हो तो उसे भी योजनाओं का लाभ दिलाने की प्रभावी कार्यवाही की जाए। सीएम योगी ने ये निर्देश गुरुवार को गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनते हुए दिए। मंदिर परिसर स्थित महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने आयोजित जनता दर्शन में कुर्सियों पर

जनता दर्शन में 250 लोगों की समस्याएं सुनीं सीएम योगी ने, निस्तारण के लिए दिए जरूरी निर्देश

बैठाए गए लोगों तक मुख्यमंत्री खुद पहुंचे और एक-एक करके सबकी समस्याओं को सुनते हुए आश्वस्त किया हर समस्या का समयबद्ध, पारदर्शी व संतुष्टिपरक निस्तारण किया जाएगा।

जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने करीब 250 लोगों की समस्याएं सुनीं। इसमें बड़ी संख्या महिलाओं की रही। इस दौरान एक महिला ने उसके आवास निर्माण के दौरान कुछ लोगों द्वारा लिंटर डालने में बाधा उत्पन्न करने की समस्या बताई। इस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि महिला की मदद की जाए और यदि कोई विधि विरुद्ध बाधा डाल रहा हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसी तरह जमीन कब्जा करने की शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे मामलों में कड़ी कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। राजस्व व पुलिस से संबंधित मामलों में प्रभावी कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि अधिकारी जन कल्याण के कार्यों को सदैव प्राथमिकता पर रखें और हर पीड़ित की समस्या का त्वरित निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

जल जनित बीमारियों के फैलने की संभावना को कम करने के लिए 15 दिनों का अभियान शुरू करने का सरकार का आदेश

श्रीनगर, 4 सितंबर । जम्मू-कश्मीर सरकार ने बाढ़ के बाद पेयजल के संभावित प्रदूषण के कारण जल जनित बीमारियों के फैलने की संभावना को कम करने के लिए 15 दिनों का अभियान शुरू करने का आदेश दिया है।

इस संबंध में आदेश सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव पीयूष सिंगला द्वारा जारी किया गया है।

जारी आदेश के अनुसार 4 सितंबर, 2025 से 15 दिनों की अवधि के लिए जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में गहन जल गुणवत्ता परीक्षण और सुरक्षित पेयजल के सेवन की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करने सहित जल जनित बीमारियों के खिलाफ निवारक उपाय करने के लिए एक निरंतर और संगठित अभियान चलाया जाएगा। सरकार ने 15-दिवसीय अभियान चलाने के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया भी जारी की है। आदेश के अनुसार संबंधित उपायुक्तों को जिला स्तर पर अभियान के समन्वय, निगरानी और कार्यान्वयन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। आदेश के अनुसार जिला विकास आयुक्त जो जिला जल जीवन मिशन के अध्यक्ष भी हैं को जिला स्तर पर बैठकें शुरू करने और जिला स्तर पर विभिन्न विभागों को संगठित करने का दायित्व सौंपा गया है। आदेश के अनुसार उपायुक्त जिला स्तर पर अभियान का समन्वय और निगरानी करेंगे। जल शक्ति विभाग को क्षेत्र स्तर के कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी के साथ प्रयोगशालाओं के माध्यम से जल गुणवत्ता परीक्षण सुनिश्चित करने और बाढ़ के दौरान पेयजल के सुरक्षित उपभोग और भंडारण के लिए किए जाने वाले उपायों और सावधानियों के बारे में मोबाइल वैन के माध्यम से घोषणाएँ करने का कार्य सौंपा गया है।

मंडलायुक्त ने जम्मू शहर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया

जम्मू, 04 सितम्बर। मंडलायुक्त जम्मू रमेश कुमार ने भारी वर्षा और बाढ़ से गंभीर रूप से प्रभावित जम्मू शहर के क्षेत्रों का व्यापक दौरा किया। मंडलायुक्त के साथ जेपीडीसीएल के प्रबंध निदेशक, जेएमसी कमिश्नर, उपायुक्त जम्मू, पीडब्ल्यूडी, जल शक्ति, पीडीडी के मुख्य अभियंता और अन्य अधिकारी भी थे। उन्होंने बाढ़ व बारिश से प्रभावित विभिन्न

क्षेत्रों और महत्वपूर्ण अवसंरचना स्थलों का निरीक्षण किया। दौरे की शुरुआत बाहू तहसील के कालका कॉलोनी से हुई, जहाँ उन्होंने तवी तटबंध और डूबे हुए मकानों को हुए नुकसान का आकलन किया। उन्होंने नगर निगम जम्मू को प्रभावित लोगों को हर संभव मदद देने और क्षेत्र से गाद व मलबा हटाने के निर्देश दिए। इसके बाद मंडलायुक्त, अधिकारियों की टीम के साथ हर की पौड़ी स्थित जल शोधन संयंत्र पर पहुँचे। उन्हें बताया गया कि संयंत्र को आंशिक रूप से चालू किया गया है। उन्होंने जल शक्ति विभाग के मुख्य अभियंता को जल्द से जल्द संयंत्र को पूर्ण क्षमता से कार्यशील बनाने के निर्देश दिए।

कठुआ में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए केंद्र से 7 सदस्यीय आईएमसीटी की टीम कठुआ पहुंची

कठुआ, 04 सितंबर । जम्मू-कश्मीर के जिला कठुआ में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए गुरूवार को केंद्र से 7 सदस्यीय अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) की टीम कठुआ पहुंची। जिसमें प्रमुख कर्नल के.पी. सिंह सलाहकार, (संचालन एवं कमान) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी (एनडीएमए) गृह मंत्रालय नई दिल्ली मुख्य रूप से उपस्थित रहे। 7 सदस्यीय अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) की टीम के वरिष्ठ अधिकारियों ने गुरूवार को कठुआ के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। जिसमें सहार खड्ड, लखनपुर, घाटी और आसपास के प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया गया। अपने दौरा के दौरान अधिकारियों ने विभिन्न जगहों पर जाकर बाढ़ से हुई क्षति का आंकलन किया और राहत एवं पुनर्वास कार्यों की गति तेज करने पर बल दिया। टीम ने जम्मू-कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर का निरीक्षण किया, जहां बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। वहीं टीम ने प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त की और राहत कार्यों की समीक्षा की। अधिकारियों ने राहत और पुनर्वास कार्यों को गति देने पर बल दिया है। वहीं अधिकारियों ने क्षति का आंकलन करने के बाद राहत कार्यों की योजना बनाई है। प्रशासन राहत और पुनर्वास कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। ताकि भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहें।

गौरतलब हो कि केंद्र सरकार की 7 सदस्यीय टीम ने कठुआ जिले में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए दौरा किया। बाद में जिला प्रशासन के साथ बैठक कर नुकसान की स्थिति की समीक्षा की। वहीं टीम द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी, जिसके आधार पर केंद्र सरकार एक बड़ा राहत पैकेज जारी कर सकती है। अब देखना यह है कि केंद्र सरकार की ओर से क्या राहत पैकेज जारी किया जाता है।

जम्मू में जलापूर्ति बहाली के उपायों की समीक्षा : राणा

जम्मू 04 सितम्बर। जम्मू प्रांत के लोगों को सुरक्षित और विश्वसनीय पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जल शक्ति, वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण तथा जनजातीय मामलों के मंत्री जावेद अहमद राणा ने एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें जलापूर्ति बहाली से संबंधित प्रगति की समीक्षा की गई।

बैठक में हाल ही में आई अचानक बाढ़, लगातार वर्षा और भूस्खलनों से बुरी तरह प्रभावित जलापूर्ति अवसंरचना की बहाली की स्थिति का आकलन किया गया।

बैठक के दौरान मंत्री ने जम्मू शहर की प्रमुख जलापूर्ति व्यवस्थाओं की समीक्षा की और जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों व इंजीनियरों के अथक प्रयासों की सराहना की। उन्होंने विशेष

रूप से धौंतली स्थित तवी फ़िल्ट्रेशन प्लांट को देर रात सफलतापूर्वक पुनः चालू करने के कार्य की प्रशंसा की। उन्होंने निर्देश दिया कि इस प्लांट से प्राप्त स्वच्छ पानी पंजतीर्थी, मुबारक मंडी, उस्ताद मोहल्ला, कची छावनी, जैन बाज़ार, जुलाका मोहल्ला और अन्य क्षेत्रों में पहुँचाया जाए। बैठक में सितली से लोहर तक 600 मिमी डायामीटर राइजिंग मेन पाइपलाइन की स्थिति की भी समीक्षा की गई, जो हाल की आपदा में गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई थी। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बहाली कार्यों में तेजी लाई जाए ताकि जलापूर्ति जल्द से जल्द सामान्य हो सके। उन्होंने जनकपुरी, रूपनगर, बनतालाब, केरन स्वर्ण विहार, मुठी और इंद्रा कॉलोनी जैसे क्षेत्रों में पूर्ण जलापूर्ति बहाल करने के निर्देश दिए, जहाँ प्रा.तिक आपदा के बाद जलापूर्ति बाधित रही है।

सितली-मान्डा राइजिंग मेन पाइपलाइन की स्थिति का संज्ञान लेते हुए मंत्री ने इंजीनियरिंग टीमों को चौबीसों घंटे कार्य कर इसे शीघ्र बहाल करने के सख्त निर्देश दिए, क्योंकि यह लाइन शहर के पुराने इलाके, न्यू प्लॉट, रेहाडी, बख्शी नगर और आस-पास के क्षेत्रों को जलापूर्ति करती है। मंत्री को बताया गया कि जम्मू में 255 ट्यूबवेल्स में से 240 वर्तमान में चालू हैं, जबकि शेष 15 को प्राथमिकता पर बहाल किया जा रहा है और अगले दो दिनों में पूरा कर लिया जाएगा।

गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों में तात्कालिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मंत्री ने 90 जल टैंकरों के बेड़े को तैनात करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने विभाग को निर्देश दिया कि शिकायतों और जन-समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए 24 घंटे नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाए।

गुरु ब्रम्हा,गुरु विष्णु,गुरु देवो महेश्वरा,
गुरु शक्षत प्रम्ब्रम्हा तस्मेश्री गुरवे नमः
....गुरु दिवश के अवसर पर में अपने गुरु रूपी माता और पिता को प्रणाम करते हुए अपने सभी साथियो को हार्दिक शुभकामनाये

गुरू दिवस

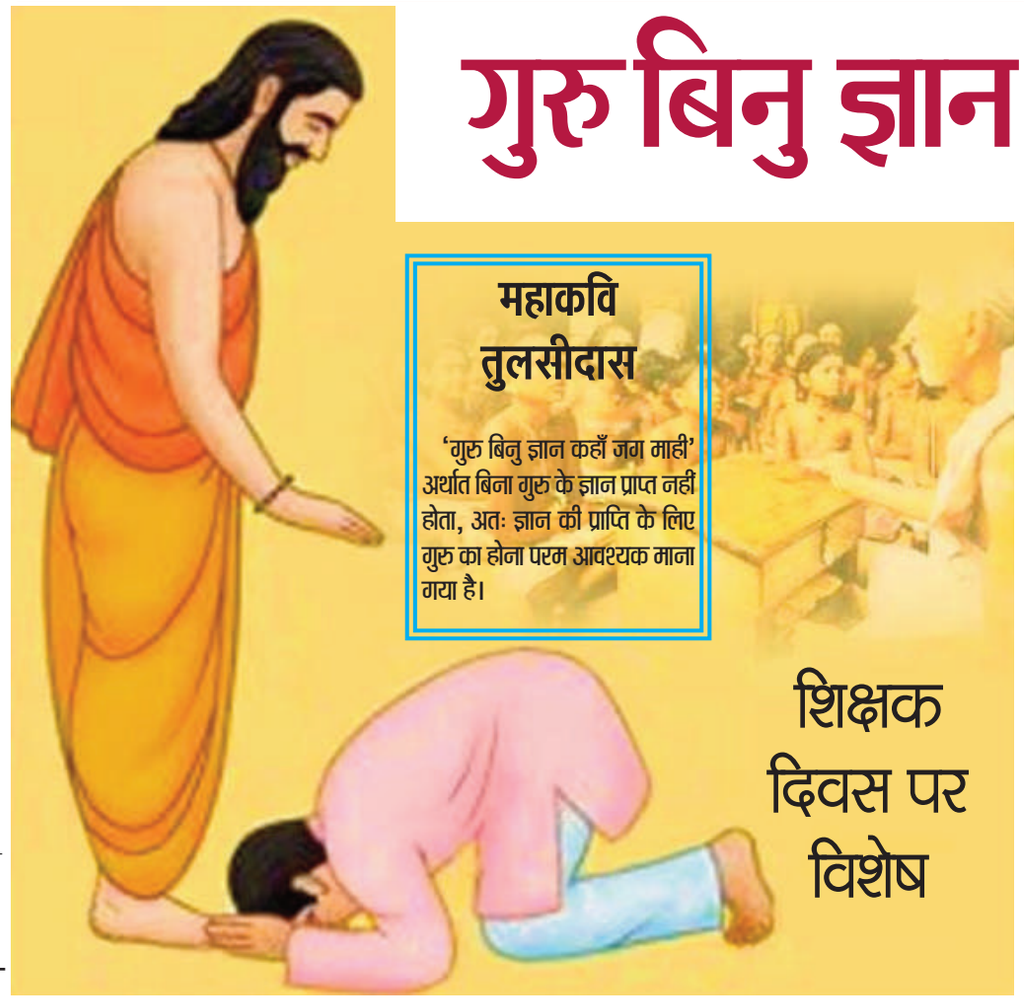

गुरु बिनु ज्ञान कहाँ जग माही

महाकवि तुलसीदास

'गुरु बिनु ज्ञान कहाँ जग माही' अर्थात बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं होता, अतः ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु का होना परम आवश्यक माना गया है।

शिक्षक दिवस पर विशेष

'अध्यापक राष्ट्र की संस्कृति के चतुर माली होते हैं। वे संस्कारों की जड़ों में खाद देते हैं और अपने श्रम से उन्हें सींचकर शक्ति में निर्मित करते हैं।' महर्षि अरविंद का उक्त कथन शिक्षक की गरिमा के सर्वथा अनुकूल ही है। शिक्षक राष्ट्र निर्माता है और राष्ट्र के निर्माण की प्रत्येक प्रक्रिया में शिक्षकीय महत्व को नकारा नहीं जा सकता ।

उर्वरायुक्त पारिवारिक धरातल पर शिक्षक संस्कारित ज्ञान की फसल बोता है और स्वच्छ एवं स्वस्थ क्षेत्रीय वातावरणीय जलवायु में श्रेष्ठता रूपी नागरिक की उन्नत उपज देता है। इस दृष्टि में शिक्षक संस्कारों का पोषक है। सही अर्थों में राष्ट्र की संस्कृति का कुशल शिल्पी है, जो संगठित, धैर्यवान, संस्कारवान, विवेकवान युवा शक्ति का निर्माण करता है। शिक्षक संस्कृति से तादात्म्य स्थापित कर शिक्षार्थी में ज्ञान के गरिमामय पक्ष का बीजारोपण करता है। फलस्वरूप शिक्षार्थी में शिक्षा के प्रति गहन अभिरुचि जाग्रत होती है। शिक्षक वह सेतु है, जो शिक्षार्थी को शिक्षा के उज्ज्वल पक्षों से जोड़ता है। संस्कारित शिक्षार्थी शिक्षा के उपवन को अपने ज्ञान-पुष्प की सुरभि से महकाते हैं तथा परिवार, समाज एवं राष्ट्र को गौरवान्वित करते हैं।

उत्तम शिक्षा, योग्य शिक्षक और अनुशासित शिक्षार्थी ही संस्कारित, सुसभ्य और स्वच्छ-स्वस्थ समाज का निर्माण करने का सामर्थ्य रखते हैं। संस्कृति का उद्गम ही श्रेष्ठ संस्कारोंके गर्भ से होता है, जिससे सामाजिक गतिविधियों को सांस्कृतिक शक्ति का संबल प्राप्त होता है।

राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका का कोई सानी नहीं है। विद्यार्थियों में स्नेह, सद्भाव, भ्रातृत्व भाव, नैतिकता, उदारता, अनुशासन जैसे चारित्रिक सद्गुणों की समष्टि गुरु के माध्यम से ही संभव होती है। समाज-जीवन में स्नेह एवं सद्भाव तथा सामंजस्य की सद्प्रेरणा गुरु से ही प्राप्त होती है क्योंकि शिक्षा का मूल उद्देश्य ही चरित्र निर्माण करना है। शिक्षक शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का हरसंभव प्रयास करता है। शिक्षक को एक ऐसा दीपक माना गया है जो सेवापर्यंत दीप्तमान रहते हुए विद्यार्थियों के प्रगतिपथ को अपने ज्ञान का आलोक प्रदान करता रहता है।

ज्ञान दे संस्कार दे,
और बनाये शिष्यों का जीवन चमन
शीश झुकाकर करते हैं हम-सब,
ऐसे गुरू-देव को शत्-शत् नमन।

हर बर्ष की तरह इस बार भी भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉ0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस के दिन यानि 5 सितम्बर को पूरे भारतवर्ष में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। वास्तव में यह दिन गुरू-शिष्य के पवित्र रिश्ते को उजागर करता है। लेकिन वर्तमान-काल में यह दिन शिक्षक दिवस के रूप मे मनाया जाना लगा है अर्थात् शिक्षक और विद्यार्थी का दिन। गुरू और शिक्षक में बहुत अन्तर है। शिक्षक अपने विद्यार्थियों को केवल शिक्षा देता है और विद्यार्थी अपने शिक्षक से विद्या को ग्रहण करते हैं, परन्तु जो गुरू होता है वह अपने शिष्यों को शिक्षा, विद्या सहित ज्ञान देता है। ज्ञान जिसका प्रयोग शिष्य अपने सम्पूर्ण जीवन-काल तक कर सकता है। प्राचीनकाल से ही गुरूओं का बोलबाला रहा है और गुरू के दिये ज्ञान पर ही शिष्य अमल करते आए हैं। मगर गुरू शब्द ने जब से शिक्षक का रूप ले लिया है, तबसे शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच एक अलग ही अन्तर सा पैदा हो गया है। गुरूओं से हटकर शिक्षकों ने अपने मूल्यों में परिबर्तन कर लिया है। इन परिवर्तनों के कारण ही अब शिक्षकों का अपने विद्यार्थियों के प्रति उतना लगाव नही रह गया है और न ही उनके प्रति उतना निष्ठा का भाव रह गया है। इसलिए प्रत्येक शिक्षक को गुरू बनकर अपने शिष्य को गुरू-ज्ञान देना चाहिए और प्रत्येक विद्यार्थी को एक सच्चे शिष्य के रूप मे उस गुरू-ज्ञान को ग्रहण कर अपने जीवन में उतारना चाहिए। तब तो शिक्षक दिवस मनाये जाने का कोई मतलब बनता है, अन्यथा अन्य कई दिवसों की तरह यह दिवस भी सिर्फ ढोंग दिवस का ही प्रारूप बनकर रह जायेगा।

एक सच्चे शिष्य हेतु दो पंक्तियाँ प्रस्तुत है:-
बनकर दिखलाओ सच्चा शिष्य
और अर्जित करो गुरू का ज्ञान,
गुरू के ज्ञान को जीवन में उतारो
और सारे जग में बढाओ गुरू का मान।

गुरु के प्रति व्यक्त करें अपनी भावनाएं

गुरु गोविन्द दोउ खड़े काके लागु पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविन्द दियो बताय। कबीर दास द्वारा लिखी गई यह पंक्तियां जीवन में गुरु के महत्व को वर्णित करने के लिए काफी हैं। जीवन में माता-पिता का स्थान कभी कोई नहीं ले सकता क्योंकि वे ही हमें इस रंगीन खूबसूरत दुनिया में लाते हैं। उनका ऋण हम किसी भी रूप में उतार नहीं सकते लेकिन जिस समाज में हमें रहना है, उसके योग्य हमें केवल शिक्षक ही बनाते हैं। यद्यपि परिवार को बच्चे के प्रारंभिक विद्यालय का दर्जा दिया जाता है लेकिन जीने का असली सलीका उसे शिक्षक ही सिखाता है। समाज के शिल्पकार कहे जाने वाले शिक्षकों का महत्व यहीं समाप्त नहीं होता क्योंकि वह ना सिर्फ आपको सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं बल्कि आपके सफल जीवन की नींव भी उन्हीं के हाथों द्वारा रखी जाती है। इसीलिए गुरु की महत्ता को समझते हुए हर वर्ष भारत में पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस यानि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। कच्चे घड़े की भांति स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को जिस रूप में ढालो, वे ढल जाते हैं। वे स्कूल में जो सीखते हैं या जैसा उन्हें सिखाया जाता है वे वैसा ही व्यवहार करते हैं। उनकी मानसिकता भी कुछ वैसी ही बन जाती है जैसा वह अपने आसपास होता देखते हैं। सफल जीवन के लिए शिक्षा बहुत उपयोगी है जो हमें गुरु द्वारा प्रदान की जाती है। गुरु का संबंध केवल शिक्षा से ही नहीं होता बल्कि वह तो हर मोड़ पर आपका हाथ थामने के लिए तैयार रहता है। आपको सही सुझाव देता है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। गुरु-शिष्य परंपरा भारत की संस्कृति का एक अहम और पवित्र हिस्सा है, जिसके कई स्वर्णिम उदाहरण हमारे इतिहास में दर्ज हैं। लेकिन वर्तमान समय में कई ऐसे लोग भी हैं जो अपने अनैतिक कारनामों और लालची स्वभाव के कारण इस परंपरा पर गहरा आघात कर रहे हैं। 'शिक्षा' जिसे अब एक व्यापार समझकर बेचा जाने लगा है, किसी भी बच्चे का एक मौलिक अधिकार है लेकिन अपने लालच को शांत करने के लिए आज तमाम शिक्षक अपने ज्ञान की बोली लगाने लगे हैं। इतना ही नहीं वर्तमान हालात तो इससे भी बदतर हो गए हैं क्योंकि शिक्षा की आड़ में कई शिक्षक अपने छात्रों का शारीरिक और मानसिक शोषण करने को अपना अधिकार ही मान बैठे हैं। किंतु हम बात कर रहे हैं ऐसे गुरुओं की जिन्होंने हमेशा समाज के सामने एक अनुकरणीय उदाहरण पेश किया। प्राय- सख्त और अक्खड़ स्वभाव वाले यह शिक्षक अंदर से बेहद कोमल और उदार होते हैं। हो सकता है आपके जीवन में भी कभी ना कभी एक ऐसा गुरु या शिक्षक का आगमन हुआ हो जिसने आपके जीवन की दिशा बदल दी या फिर आपको जीवन जीने का सही ढंग सिखाया हो।

शिक्षक दिवस का महत्व

'शिक्षक दिवस' कहने-सुनने में तो बहुत अच्छा प्रतीत होता है। लेकिन क्या आप इसके महत्व को समझते हैं। शिक्षक दिवस माने साल में एक दिन बच्चों द्वारा टीचर्स को भेंट किया गया एक गुलाब का फूल या कोई भी गिफ्ट। नहीं यह टीचर दिवस मनाने का सही तरीका नहीं है।

टीचर्स डे हम सभी मनाते आए है। आपने भी मनाया है। हमने भी मनाया है। लेकिन इस दिन को मनाना तभी सही मायने में सार्थक सिद्ध होगा जब आप अपने टीचर के प्रति सही नजरिया रखें। पिछले कुछ ही समय में ऐसी कई घटनाएँ देश और दुनिया में घटी है जो आपके व्यवहार, वातावरण और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। चाहे वह घटना 'सभरवाल कांड' हो या फिर किसी शिक्षक द्वारा भरी क्लास में या एकांत में स्कूली छात्रा के कपड़े का नाप लेना हो। या फिर किसी शिक्षक द्वारा बच्चे के कपड़े उतारकर उसे दंडित करना हो। यह सब बातें हमें किस ओर इंगित करती है। यह समझना आज बहुत जरूरी हो गया है। या तो शिक्षक वो शिक्षक नहीं रहे जो अपने छात्रों को वह सही संस्कार दे सकें। या फिर आजकल के शिक्षकों में अहंकार, अत्याचार, ईर्ष्या और द्वेष का भाव बहुत ज्यादा मात्रा में आ गया है। यह सब मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं शिक्षकों का आदर करना नहीं जानती, या फिर मैं शिक्षकों के खिलाफ हूँ।

बात ऐसी नहीं है... रोजाना हमारे आमने-सामने, हमारे आस-पास घटित होने वाली उन घटनाओं सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है? क्या किसी भी छात्र संगठन के छात्रों द्वारा शिक्षकों को अपमानित करना, उनके साथ मारपीट करना ये वाक्या किस हद ते क सही है। अभी हाल ही में एक स्कूल 10वीं-11वीं के छात्र ने अपने टीचर की जमकर धुनाई कर दी थी। उस छात्र ने ऐसा क्यों किया यह सोचना भी एक बहुत बड़ा पहलू है। अगर हम मान भी लेते है कि हो सकता है उस बच्चे की कोई मजबूरी रही हो, या उस बच्चे को गुस्सा बहुते ज्यादा आता हो तो शिक्षक द्वारा कहीं गई बातों का, शिक्षक द्वारा` उस छात्र के साथ किए गए व्यवहार से आहत होकर उस बच्चे ने इतना घिनौना कदम उठाया। बात जो भी हो, लेकिन तरीका तो गले त ही हुआ। शिक्षक को हम विद्या का वरदान देने वाले भगवान का दर्जा देते आए है। उनके प्रति हमारे मन असीम प्यार, और स्नेह छुपा होता है।` तो फिर छात्र द्वारा अपने शिक्षक के साथ किया गया यह व्यवहार कैसा? क्या आजकल के बच्चों को स्कूलों में सही शिक्षा, सही वातावरण नहीं मिल रहा है या फिर आपके घर के संस्कारों में कुछ कमी है। जो आप जरा-जरा सी बात पर मरने-मारने पर उतारूँ हो जाते है। अगर आप शिक्षक दिवस का सही महत्व समझना चाहते है तो सर्वप्रथम आप इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि आप एक छात्र है, और अपने शिक्षक से उम्र में काफी छोटे है। और फिर हमारे संस्कार भी तो हमें यही सिखाते है कि हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। अपने गुरु का आदर-सत्कार करना चाहिए। उनकी बात को ध्यान से सुनना और समझना चाहिए। अगर आपने अपने क्रोध, ईर्ष्या को त्याग कर अपने अंदर संयम के बीज बोएँ तो निश्े चित ही आपका व्यवहार आपको बहुत ऊँचाइयों तक ले जाएगा। और तभी हमारा शिक्षक दिवस मनाने का महत्व भी सार्थक होगा।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुंद्रक – नीलम सिंह गिल द्वारा देहात संदेश, गुरूद्वारा सुंदर सिंह रोड़, जम्मू से प्रकाशित एवं नार्थलाईनस पबलिशर्स, 18-बी, फेस- 2, इंडस्ट्रियल इस्टेट, गंग्याल जम्मू से मुद्रित। संपादक– नीलम सिंह गिल। फोन नंबर : (95) 191-2574109, 2548103 RNI Regd. No: JKBIL/2004/13144 Email: dehatsandesh@gmail.com, dehatsandesh@yahoo.com, dehatsandesh@rediffmail.com

सेना ने छात्रों के लिए राष्ट्रीय एकता यात्रा को हरी झंडी दिखाई

राजौरी, 4 सितंबर (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर के युवाओं में राष्ट्रीय एकता और एकता को बढ़ावा देने के प्रयास में भारतीय सेना ने क्षेत्र के 20 छात्रों और 2 शिक्षकों के लिए एक राष्ट्रीय एकता यात्रा को हरी झंडी दिखाई है। नरियां (राजौरी) से आए इस दल ने एक समृद्ध यात्रा शुरू की है जो उन्हें चेन्नई, त्रिवेंद्रम, कन्याकुमारी और दिल्ली सहित भारत के प्रमुख शहरों की सैर कराएगी।

इस यात्रा का उद्देश्य छात्रों को विविध संस्कृतियों, इतिहास और शैक्षिक स्थलों को जानने का एक अनूठा अवसर प्रदान करना है। इस यात्रा के दौरान छात्र चेन्नई स्थित प्रतिष्ठित अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी (ओटीए) सहित महत्वपूर्ण स्थानों का दौरा करेंगे जहाँ वे पासिंग आउट परेड देखेंगे। उन्हें भारत के राष्ट्रपति और थल सेनाध्यक्ष (सीओएएस) से बातचीत करने का भी अवसर मिलेगा जिससे उन्हें देश के नेतृत्व और शासन के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त होगी।यह पहल जम्मू-कश्मीर के युवाओं के क्षितिज को व्यापक बनाकर समावेशिता को बढ़ावा देकर और राष्ट्रीय गौरव की भावना का संचार करके उन्हें सशक्त बनाने की सेना की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। छात्रों को भारत की समृद्ध विविधता से परिचित कराकर सेना का उद्देश्य एकता और सहयोग के बंधन को मज़बूत करना है और यह सुनिश्चित करना है कि भावी पीढ़ी एक समृद्ध और सामंजस्यपूर्ण भारत के निर्माण के लिए आवश्यक ज्ञान और अनुभव से सुसज्जित हो।

कठुआ में मूसलाधार बारिश के बाद डीसी ने जल प्रदूषण के खिलाफ सख्त कदम उठाने के दिए निर्देश

कठुआ, 04 सितंबर (हि.स.)। जिले में लगातार बारिश और अचानक आई बाढ़ के मद्देनजर जन स्वास्थ्य की सुरक्षा के उपायों की समीक्षा के लिए डीसी राजेश शर्मा ने एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। डीसी ने जल शक्ति विभाग को प्रयोगशाला टीमों और क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के माध्यम से जल गुणवत्ता परीक्षण में तेजी लाने, जल स्रोतों की बार-बार सफाई सुनिश्चित करने और मोबाइल वैन तथा रेडियो जिंगल्स के माध्यम से व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को जलजनित रोगों के बारे में समुदायों को तुरंत सचेत करने, आवश्यक जाँच करने और सुरक्षित जल उपभोग एवं स्वच्छता प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए कहा गया। सामुदायिक भागीदारी पर जोर देते हुए डीसी ने ग्रामीण विकास विभाग को गाँवों में विशेष स्वच्छता अभियान आयोजित करने, पारंपरिक जल स्रोतों पर ध्यान केंद्रित करने और लोगों को जल, स्वच्छता और स्वच्छता मानकों के बारे में शिक्षित करने का आह्वान किया। उच्चधिद्यालय शिक्षा विभाग को स्कूलों और कॉलेजों में जल गुणवत्ता परीक्षण के प्रदर्शन सत्र आयोजित करने और छात्रों को निवारक स्वास्थ्य उपायों के बारे में जागरूक करने के निर्देश भी दिए गए। समाज कल्याण विभाग को आंगनवाड़ी केंद्रों में जल गुणवत्ता परीक्षण करने और विशेष स्वच्छता अभियानों के साथ-साथ सामान्य वाश प्रथाओं को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार सक्रिय और समन्वित प्रतिक्रिया की आवश्यकता पर जोर देते हुए डीसी ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि वे जल प्रदूषण के खतरे को कम करने और पूरे जिले में स्वास्थ्य संबंधी खतरों को रोकने के लिए सौंपी गई भूमिकाओं को प्राथमिकता के आधार पर लागू करें।

रमन भल्ला ने जम्मू-कश्मीर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया

जम्मू, 4 सितंबर (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री रमन भल्ला ने आज जम्मू के बाढ़ प्रभावित इलाकों का व्यापक दौरा किया जहाँ उन्होंने निवासियों से बातचीत की और हाल ही में आई बाढ़ से हुए व्यापक नुकसान का आकलन किया। राहत और पुनर्वास प्रयासों की धीमी गति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए भल्ला ने प्रशासन से इस संकट से निपटने के लिए तेज़ी और ज़िम्मेदारी से काम करने की पुरज़ोर अपील की।

अपने दौरे के दौरान भल्ला ने देखा कि बाढ़ के दस दिन से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी कई इलाकों की गलियों और घरों में मलबा (कीचड़ और मलबा) जमा है। भल्ला ने कहा स्थिति गंभीर बनी हुई है। मलबा साफ़ न होने के कारण निवासियों को सामान्य जीवन फिर से शुरू करने में मुश्किल हो रही है। मशीनरी और मानव संसाधन की भारी कमी है। अधिकारियों को तुरंत संसाधन जुटाने चाहिए, भले ही इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग से भारी मशीनरी हटानी पड़े और संबंधित संगठनों से सहायता लेनी पड़े।

उन्होंने आगे कहा कि नालों में बढ़ता जलस्तर लगातार ख़तरा पैदा कर रहा है, जिसके लिए तत्काल निवारक उपाय ज़रूरी हैं। भल्ला ने उन परिवारों की दुर्दशा पर भी प्रकाश डाला जो अपने स्थानीय श्मशान घाटों में अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बाढ़ के कारण कई श्मशान घाट अनुपयोगी हो गए हैं। उन्होंने कहा, फ्रयह बेहद दुखद है कि लोगों को दाह संस्कार के लिए दूर-दराज़ के गाँवों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यह प्रभावित परिवारों के लिए बुनियादी सम्मान सुनिश्चित करने में सरकार की तैयारी की कमी को दर्शाता है।

कांग्रेस नेता ने सड़क संपर्क तत्काल बहाल करने, बाढ़ प्रभावित निचले इलाकों में चिकित्सा दल तैनात करने और तत्काल स्वच्छता अभियान चलाने की माँग की। उन्होंने आगाह करते हुए कहा स्वच्छता, सफाई और जन स्वास्थ्य गंभीर खतरे में हैं। समय पर चिकित्सा सहायता के बिना जलजनित बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है।

सरकारी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, अखनूर के लिए 35 पीजी सीटें स्वीकृत

जम्मू, 4 सितंबर (हि.स.)। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में आयुर्वेद की जड़ें मज़बूत करने के लिए आयुष मंत्रालय ने सरकारी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, अखनूर के लिए 35 आयुर्वेद पीजी सीटें स्वीकृत की हैं।

यह जम्मू-कश्मीर के लिए पहली बार है और केंद्र शासित प्रदेश में आयुर्वेद पद्धति अपनाने के इच्छुक लोगों के लिए एक बड़ा तोहफ़ा है।

आयुर्वेद, पारंपरिक चिकित्सा पद्धति ने वैश्विक लोकप्रियता हासिल की है और दुनिया भर के लोग अपनी स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतों, तन, मन और आत्मा के स्वास्थ्य और विभिन्न रोगों के प्रबंधन के लिए आयुर्वेद तकनीकों को अपना रहे हैं।

जीएएमसी अखनूर में 35 सीटों वाले 7 नए पीजी डिग्री प्रोग्राम जम्मू-कश्मीर के स्वास्थ्य ढांचे को और मज़बूत करेंगे और पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को लोकप्रिय बनाएंगे।

आयुर्वेद पद्धतियों और अनुसंधान में मानव संसाधन और सहयोग निवारक और समग्र देखभाल को बढ़ावा देने में मदद करेंगे।

आप नेता ने जम्मू-कश्मीर व पंजाब की बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की

जम्मू, 4 सितंबर (हि.स.)। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और समाजसेवी गुरमीत सिंह बाग़ी ने जम्मू-कश्मीर और पंजाब में आई भीषण बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इससे प्रभावित परिवारों को मानव जीवन, मकानों, ढांचे और अन्य नुकसानों के लिए उचित मुआवजा मिल सकेगा। बाग़ी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उसने बाढ़ पीड़ितों को राहत और पुनर्वास देने में पूरी तरह विफलता दिखाई है। उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार तत्काल जम्मू-कश्मीर और पंजाब के लिए विशेष बाढ़ राहत पैकेज की घोषणा करे और प्रभावित लोगों के पुनर्वास की ठोस व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

बाढ़ से टूटा संपर्क, सेना ने कुछ ही घंटों में बनाया पैदल पुल, सात हजार से अधिक लोगों को मिली राहत

अमीर इक़बाल ख़ान

भद्रवाह, 4 सितम्बर। तबाही मचाने वाली अचानक आई बाढ़ के बाद भारतीय सेना की 4 राष्ट्रीय राइफल्स ने एक बार फिर जन-जन का विश्वास जीता है। गुरुवार को भद्रवाह स्थित जवानों ने फौरन मोर्चा संभालते हुए मुष देव नाले पर नेहरू नदी के ऊपर एक अस्थायी पैदल पुल तैयार कर दिया, जिससे बाढ़ से कटे गांवों की जिंदगी में फिर से रौनक लौट आई।

तेज़ धारा में बह जाने से पुराने पुल टूट गए थे, जिससे शेराखी, कत्यारा, भेड़ा, थानाला, बमलाखी, मुष देव नाला समेत कई बस्तियां पूरी तरह से कट गई थीं। आवाजाही रुक जाने से ग्रामीणों की मुश्किलें दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही थीं। ऐसे में सेना की यह त्वरित कार्रवाई न केवल इन गांवों को जोड़ने का काम कर गई बल्कि स्थानीय लोगों के दिलों को भी छू गई।

नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड ने जीएसटी-2 सुधारों का स्वागत किया

जम्मू, 4 सितंबर (हि.स.)। नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के राष्ट्रीय बोर्ड सदस्य तथा एफटीआईआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजय बंसल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री का अभिनव जीएसटी-2 सुधारों के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि ये सुधार भारतीय अर्थव्यवस्था को नई गति देंगे और आम नागरिक की क्रय शक्ति में वृद्धि करेंगे। डॉ. बंसल ने कहा कि जीएसटी-2 लागू होने से कर प्रणाली और अधिक सरल होगी, अनुपालन का बोझ घटेगा और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। कर ढांचे को सरल बनाने और छूटों को कम करने से विशेषकर छोटे और मझोले उद्योगों को लाभ होगा। उनके टैक्स दायित्व कम होंगे जिससे प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ेगी।

रावी के तेज बहाव से जमीन का कटाव जोरो पर

कठुआ/लखनपुर, 04 सितंबर (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में रावी दरिया का जल स्तर बढ़ने से सरकारी इमारतों को खतरा हो गया है। हाल ही में आई बाढ़ के कारण पंजाब की ओर जाने वाला पुराना पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, और अब पशुपालन विभाग की इमारत पर भी खतरा मंडरा रहा है। रणजीत सागर बांध से रोजाना हजारों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे रावी दरिया का जल स्तर बढ़ रहा है। हर रोज लगातार रणजीत सागर बांध से हजारों क्यूसेक पानी छोड़ा जाने से रावी दरिया का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। जिसके कारण जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में हाल ही में रावी दरिया में आई बाढ़ की वजह से पंजाब की ओर जाने वाला पुराना पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, इसके बाद अब पुल के साथ लगते पशुपालन विभाग कार्यालय के साथ-साथ अन्य सरकारी भवनों पर खतरा मंडरा रहा है। दरअसल हिमाचल और जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से रावी दरिया पर बने सभी बांध खतरे के निशान से ऊपर है, जिसके चलते सभी बांध पानी छोड़ रहे हैं। वही जम्मू-कश्मीर और पंजाब के बीचोबीच बने रणजीत सागर बांध से छोड़े जा रहे पानी से रावी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है जिससे लखनपुर स्थित सरकारी भवनों के पास पानी के तेज बहाव से जमीन का कटाव हो रहा है। गुरुवार शाम को पशुपालन विभाग की इमारत के पिलर जमीन कटाव के चलते सामने दिखाई देने लगे हैं। इसी के साथ लगती है एक और इमारत के भी पिलर सामने दिखाई दे रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर कदम उठाते हुए इन इमारतों को खाली करवा लिया है। हालांकि गुरुवार को केंद्र से आई टीम ने भी जम्मू कश्मीर और पंजाब सरकार को मिलकर युद्धस्तर पर काम करने के निर्देश दिए थे ताकि इन इमारत को बचाया जाए। वहीं लखनपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और पंजाब सरकार की ओर से युद्ध स्तर पर काम जारी है, लेकिन रावी में बढ़ते जलस्तर की वजह से बचाव कार्य में काफी वादा आ रही है।

बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने से तबाही पर नेकां ने केंद्र से मांगा व्यापक राहत पैकेज

जम्मू, 4 सितंबर (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के प्रांतीय अध्यक्ष रत्तन लाल गुप्ता ने जम्मू संभाग में बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने से हुई भारी तबाही को देखते हुए तुरंत व्यापक राहत एवं पुनर्वास पैकेज की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस प्राकृतिक आपदा ने पूरे क्षेत्र को गहरे संकट में डाल दिया है और लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। एनसी मुख्यालय शेर-ए-कश्मीर भवन, जम्मू से जारी प्रेस विज्ञप्ति में गुप्ता ने बताया कि आपदा में सैकड़ों लोगों की जान गई है और सार्वजनिक व निजी ढांचे को गंभीर नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि स्कूल, अस्पताल, सड़कें, पुल और बिजली-पानी की आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है, जबकि कई ढांचे धंस गए या पूरी तरह बह गए हैं। उन्होंने किसानों की तबाही का जिक्र करते हुए कहा कि खड़ी फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं और छोटे व्यापारी व दुकानदार भी भारी संकट में हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था तथा नालों का तंत्र पूरी तरह ठप हो गया है। इसी तरह की तबाही कश्मीर संभाग में भी सामने आई है। प्रारंभिक आकलन के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में कुल नुकसान डेढ़ लाख करोड़ रुपये से अधिक है। गुप्ता ने कहा कि सीमित संसाधनों के चलते जम्मू-कश्मीर इस आपदा से अकेले नहीं निपट सकता। केंद्र सरकार द्वारा अब तक जारी धनराशि एक पुल तक के पुनर्निर्माण के लिए भी पर्याप्त नहीं है। उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार तत्काल प्रभाव से राहत एवं पुनर्वास पैकेज की घोषणा करे, ताकि प्रभावित समुदायों को जीवनयापन और पुनर्निर्माण में सहायता मिल सके।

7 सितंबर को जम्मू में लगेगा खग्रास चंद्रग्रहण, जानिए क्या पड़ेगा प्रभाव और सावधानियाँ

जम्मू, 4 सितंबर (हि.स.)। आगामी 7 और 8 सितंबर की मध्यरात्रि भाद्रपद पूर्णिमा पर खग्रास चंद्रग्रहण लगेगा, जो पूरे भारत में दृश्यमान होगा। श्री कैलख ज्योतिष एवं वैदिक संस्थान ट्रस्ट, रायपुर (ठठर), जम्मू-कश्मीर के अध्यक्ष और ज्योतिषाचार्य महंत रोहित शास्त्री ने बताया कि यह ग्रहण 7 सितंबर की रात 9:56 बजे शुरू होकर 8 सितंबर की सुबह 1:27 बजे समाप्त होगा। ग्रहण का खग्रास चरण रात 11:01 बजे प्रारंभ होकर 12:23 बजे तक रहेगा। सूतक काल 7 सितंबर को दोपहर 12:56 बजे से ही प्रभावी हो जाएगा। महंत शास्त्री ने कहा कि यह चंद्रग्रहण पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र और कुंभ राशि में घटित होगा तथा भारत के अलावा एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, पश्चिमी उत्तरी अमेरिका, फिजी और अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में भी देखा जा सकेगा। ज्योतिषीय दृष्टि से यह पर्वतीय क्षेत्रों, पश्चिमी प्रांतों, पशुपालकों और कला-संगीत से जुड़े व्यक्तियों के लिए कष्टकारी रहेगा, वहीं कुछ राशियों को धन लाभ और उन्नति भी होगी।

उत्तर रेलवे

खुली निविदा सूचना

व. मंडल विद्युत अभियंता/टी.आर.डी, उ.रे., फिरोजपुर के लिए और भारत के राष्ट्रपति की ओर से ई-निविदाएं अंतिम तिथि 26.09.2025 को 15:00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं। निविदाकारक अपने मूल/संशोधित निविदा बंद होने की तारीख 26.09.2025 को 15:00 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं। मैनुअल प्रस्ताव इस निविदा के लिए मान्य नहीं है।

क्र. सं.	टेंडर संख्या	कार्यों का विवरण	अनुमानित लागत (Rs.)	टेंडर की कीमत (Rs.)	निविदा की समापन तिथि व समय	बयाना राशि # (Rs.)	कार्य की अवधि	टेंडर खुलने की तिथि एवं समय	वेब साईट
1.	716-टी.आर.डी- फिरोजपुर -2025-26	फिरोजपुर डिवीजन में ASR-KEMK सेक्शन पर तरनतारन (TTO) पर गतिशीलता में सुधार के लिए लोडिंग लाइन नंबर 4 पर रिसेप्शन और डिस्पैच सुविधा में टीआरडी कार्य	88,61,070.36	शून्य	26.09.2025 15:00 बजे तक	1,77,200/-	06 माह	26.09.2025 15:00 बजे के बाद	www.ireps.gov.in
2.	717-टी.आर.डी- फिरोजपुर -2025-26	फिरोजपुर डिवीजन में GZS यार्ड में पीएसआर को हटाने और एक साथ रिसेप्शन की सुविधा के संबंध में टीआरडी कार्य	70,99,161.06	शून्य	26.09.2025 15:00 बजे तक	1,42,000/-	06 माह	26.09.2025 15:00 बजे के बाद	www.ireps.gov.in
कार्य की समान प्रकृति (उपरोक्त दोनों निविदा सं. 716-टी.आर.डी.-फिरोजपुर-2025-26 एवं 717-टी.आर.डी. - फिरोजपुर-2025-26 के लिए): "50 हर्ट्ज, सिंगल फेज 25 केवी एसी ओएचई का डिजाइन, आपूर्ति, निर्माण परीक्षण और कमीशनिंग" (संदर्भ: Pr-CEE/NR के पत्र संख्या 181-इलेक्ट/टीआरडी/189/भाग II, दिनांक 29.07.2021 का ओएचई कार्य का क्रम संख्या 1.1).								
3.	718-टी.आर.डी- फिरोजपुर -2025-26	फिरोजपुर मंडल के ADEN-I/ASR सेक्शन में अमृतसर रेलवे स्टेशन पर वाशिंग लाइन नंबर 4 और सिक लाइन/एसी पिट के सुधार के संबंध में टीआरडी कार्य	40,10,829.18	शून्य	26.09.2025 15:00 बजे तक	80,200/-	06 माह	26.09.2025 15:00 बजे के बाद	www.ireps.gov.in

#निविदाकर्ता कृपया ध्यान दें कि बोली सुरक्षा के बिना प्राप्त प्रस्ताव या तो ई-पेमेंट गेटवे के माध्यम से नकद में या भारत के किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से बैंक गारंटी बांड के रूप में या निविदा दस्तावेजों में उल्लिखित (अनुलग्नक-21 के अनुसार) एक अवधि के लिए वैध हैं। बोली की वैधता अवधि के बाद 90 दिनों के लिए, अपूर्ण और अमान्य प्रस्ताव के रूप में माना जाएगा और जिसके लिए ठेकेदार का रेलवे पर कोई दावा नहीं होगा।

सं. 716, 717 एवं 718-टी.आर.डी.-फिरोजपुर-2025-26, दिनांक 07.09.2025 2682/25

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

बाढ़ प्रभावित इलाकों में नेकां का मास कांटैक्ट प्रोग्राम शुरू

जम्मू, 4 सितंबर (हि.स.)। जम्मू क्षेत्र में हाल ही में आई बाढ़ की तबाही के बीच नेशनल कांफ्रेंस ने राहत और पुनर्वास कार्यों को गति देने के लिए मास कांटैक्ट प्रोग्राम की शुरुआत की। यह पहल प्रांतीय अध्यक्ष एडवोकेट रतन लाल गुप्ता के निर्देश और पार्टी अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला तथा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अगुवाई में शुरू की गई है। कार्यक्रम के पहले दिन प्रांतीय संयुक्त सचिव अंशु अभ्रोल और जोनल सचिव डॉ. विकास शर्मा ने वार्ड नंबर 40 के पूंछ हाउस और कबीर बस्ती का दौरा किया। इन क्षेत्रों में बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है। दौरे के दौरान दोनों नेताओं ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं और मौके पर राहत कार्यों का समन्वय किया। उन्होंने घरों, कारोबार और बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान का जायज़ा लेते हुए संबंधित विभागों को तुरंत कार्रवाई कर आवश्यक सुविधाएं बहाल करने के निर्देश दिए।

नेशनल कांफ्रेंस नेताओं ने आश्वासन दिया कि पार्टी हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगी और प्रभावित परिवारों को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल तात्कालिक राहत पहुंचाना है, बल्कि जनता से फीडबैक लेकर भविष्य की राहत और पुनर्वास नीतियों को और प्रभावी बनाना भी है। नेताओं ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता लगातार सभी प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे और वहां की स्थिति का आकलन शीर्ष नेतृत्व को सौंपेंगे ताकि ज़मीनी स्तर पर ठोस कदम उठाए जा सकें। स्थानीय निवासियों ने इस पहल का स्वागत करते हुए एनसी नेताओं का आभार जताया कि उन्होंने कठिन समय में उनके बीच आकर सहयोग का आश्वासन दिया। जैसे-जैसे बाढ़ का पानी घट रहा है, अब फोकस पुनर्वास और पुनर्निर्माण पर है, और नेशनल कांफ्रेंस का यह मास कांटैक्ट प्रोग्राम इसमें अहम भूमिका निभाएगा।

एबीवीपी ने की सिविल जज परीक्षा स्थगित करने की मांग, विपक्ष के नेता और बार एसोसिएशन अध्यक्ष ने दिया समर्थन

जम्मू, 4 सितंबर (हि.स.)। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) जम्मू-कश्मीर के राज्य सचिव सन्नक श्रीवत्स के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने वीरवार को विपक्ष के नेता और बार एसोसिएशन जम्मू के अध्यक्ष से मुलाकात कर 21 सितंबर 2025 को प्रस्तावित सिविल जज परीक्षा स्थगित करने की मांग उठाई। सन्नक श्रीवत्स ने कहा कि हाल ही में आई बाढ़ जैसी आपदा ने छात्रों के जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है, जिसके चलते उनके लिए परीक्षा की तैयारी करना बेहद कठिन हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में निष्पक्षता और समान अवसर सुनिश्चित करना अनिवार्य है, इसलिए वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए परीक्षा को टालना आवश्यक है।

प्रतिनिधिमंडल ने विपक्ष के नेता और बार अध्यक्ष से इस मुद्दे पर छात्रों का समर्थन करने की अपील की। एबीवीपी ने जोर देकर कहा कि परीक्षा स्थगन से समानता और क़ानून के शासन के सिद्धांतों की रक्षा होगी। विपक्ष के नेता और बार अध्यक्ष ने एबीवीपी की इस मांग का समर्थन करते हुए भरोसा दिलाया कि वे इसे संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाएंगे। एबीवीपी ने उनके सकारात्मक रुख की सराहना करते हुए कहा कि संगठन छात्रों के हितों की रक्षा के लिए लगातार प्रयासरत रहेगा और आशा करता है कि आयोग जल्द ही छात्रों की समस्याओं को देखते हुए उचित निर्णय लेगा।

चिट्टे के साथ एक नशा तस्कर गिरफ्तार

कठुआ, 04 सितंबर (हि.स.)। नशे के खिलाफ जारी अभियान के तहत एसएसपी कठुआ के समग्र पर्यवेक्षण में थाना कठुआ की पुलिस पोस्ट घाट्टी के अधिकार क्षेत्र में 5.09 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) के साथ एक ड्रग तस्कर को मौके पर ही गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार कठुआ थाना की चैकी घट्टी के प्रभारी पीएसआई रजत कोतवाल के नेतृत्व में एक पुलिस दल ने डीएसपी मुख्यालय कठुआ रविंदर सिंह के निकट पर्यवेक्षण में डबवाल रेलवे ट्रैक के पास लगाए गए नियमित नाके के दौरान एक व्यक्ति को जांच के लिए रोका। जांच के दौरान उसके कब्जे से 05.09 ग्राम हेरोइन चिट्टा जैसा पदार्थ बरामद किया गया। इसके बाद बरामद सभी नशीले पदार्थ को जब्त कर एक नशा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया। तदनुसार, कठुआ पुलिस स्टेशन में एफआईआर संख्या 422/2025, धारा 8/21/22 एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया और आगे की जाँच जारी है।

संपादकीय

पीएम केयर्स फंड चुप क्यों है!

देश, खासकर जम्मू-कश्मीर समेत उत्तर भारत के राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित लोग, इस बात पर विचार करके खुद को अलग-थलग महसूस कर रहे होंगे कि भारत में ऐसी आपदा से निपटने के लिए एक समर्पित पीएम केयर्स फंड होने के बावजूद, इस फंड के संचालक, जिन्हें देश के ही लोग अपने वेतन का कुछ हिस्सा दान देकर जुटाते हैं, इस तथाकथित सार्वजनिक फंड के ज़रिए किसी भी तरह की राहत की घोषणा नहीं कर रहे हैं।

यह सोचने वाली बात है कि इस फंड का इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाएगा, जब वित्तीय सहायता के अभाव में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर जैसे तीन राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के हज़ारों लोग केंद्र से कोई बड़ी राहत न मिलने के कारण बुरी तरह पीड़ित हैं।

यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि उक्त राहत कोष कथित तौर पर किसी भी प्रकार की सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति या किसी भी अन्य प्रकार की आपात स्थिति, आपदा या संकट, चाहे वह मानव निर्मित हो या प्राकृतिक, से संबंधित राहत या सहायता प्रदान करने और उसका समर्थन करने के लिए बनाया गया था, जिसमें स्वास्थ्य सेवा या दवा सुविधाओं का निर्माण या उन्नयन, अन्य आवश्यक बुनियादी ढाँचा, प्रासंगिक अनुसंधान के लिए धन या किसी अन्य प्रकार का समर्थन, और वित्तीय सहायता प्रदान करना, धनराशि का भुगतान प्रदान करना या ऐसे अन्य कदम उठाना शामिल है जो न्यासी बोर्ड द्वारा प्रभावित आबादी के लिए आवश्यक समझे जाएँ।

यह आश्चर्यजनक है कि बाढ़ और बादल फटने से तबाह हुए राज्यों में प्रभावित आबादी आज जिस भारी दुविधा का सामना कर रही है, उसके बावजूद, इसके संचालक विचलित नहीं हैं और उनका मानना ??है कि प्रभावित राज्यों के लोग भारत के प्रधानमंत्री के नाम पर गठित इस प्रतिष्ठित राहत कोष से राहत पाने के योग्य नहीं हैं।

यह ध्यान देने योग्य है कि इस कोष को एक समर्पित राष्ट्रीय कोष की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था, जिसका प्राथमिक उद्देश्य किसी भी प्रकार की आपातकालीन या संकट की स्थिति से निपटना था, जैसे कि COVID-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति, और प्रभावितों को राहत प्रदान करना, लेकिन ऐसे समय में जब बड़ी संख्या में आबादी पीड़ित है, देश के मामलों को चलाने वालों की ओर से अभूतपूर्व बाढ़ के कारण दुख और संकट में लोगों को बचाने के लिए इस राहत स्रोत को खोलने के बारे में कोई शब्द नहीं है।

विनाशकारी विकास की देन हैं ये कुदरती आपदाएं

पर्यावरण संरक्षण संबंधी कानूनों के तहत पहाड़ी और वन्य इलाकों में कोई भी औद्योगिक या विकास परियोजना शुरू करने के लिए स्थानीय पंचायतों की अनुमति जरुरी होती है

पर्यावरण संरक्षण संबंधी कानूनों के तहत पहाड़ी और वन्य इलाकों में कोई भी औद्योगिक या विकास परियोजना शुरू करने के लिए स्थानीय पंचायतों की अनुमति जरुरी होती है, लेकिन राज्य सरकारें जमीन अधिग्रहण संबंधी अपने विशेषाधिकारों का इस्तेमाल करते हुए विकास के नाम पर आम तौर पर कंपनियों के साथ खड़ी नजर आती हैं।पिछले महीने उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने से भीषण तबाही हुई थी तो सरकार के विकास प्रेमी राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासन तंत्र और मीडिया ने मोटे तौर पर यही माना था कि उत्तराखंड में ऐसी कुदरती आपदाएं आती रहती हैं, लेकिन बात इतनी सामान्य नहीं है। दरअसल हिमालय के किसी भी क्षेत्र में आने वाली आपदा आम तौर पर स्थानीय नहीं होती है। उत्तराखंड के साथ ही पिछले एक हफ्ते से ज्यादा समय से पंजाब, कश्मीर, और हिमाचल प्रदेश में भीषण बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने से मची तबाही पिछले महीने उत्तरकाशी में आई आपदा का ही विस्तार है। ताजा आपदा में गांव के गांव डूब गए हैं, लाखों लोग बेघर हो गए हैं और करीब 500 लोगों के मारे जाने की खबर है। मारे गए लोगों का यह आंकड़ा सरकारी है, वास्तविक मृतक संख्या कहीं ज्यादा ही होगी।इन आपदाओं को जलवायु चक्र में हो रहे परिवर्तन से भी जोड़कर देखा जाता है लेकिन असल में यह मनुष्य की खुदगर्जी और विनाशकारी विकास की भूख से उपजा संकट ही है। इस विकास के तहत पर्वतीय इलाकों में बड़े-बड़े बांध, बड़े-बड़े पॉवर प्रोजेक्ट, सीमेंट कांक्रीट की भारी-भरकम इमारतें, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऑल वेदर रोड, मौज-मस्ती के लिए सितारा होटल, रिसोर्ट्स आदि आए दिन तबाही का सबब बन रहे हैं। अभी तो यह तबाही महज पहाड़ों तक सीमित है परन्तु विशेषज्ञों का मानना है कि यह जल्दी ही तराई के इलाकों तक पहुंचने वाली है और देश के बाकी हिस्से भी इससे अछूते नहीं रहेंगे।पिछली बार जब 2013 में केदारनाथ और 2014 में कश्मीर में बाढ़ से भीषण विनाश हुआ था, तब तमाम अध्ययनों के आधार पर चेतावनी दी गई थी कि अगर पहाड़ों की अंधाधुंध कटाई और नदियों के बहाव से अतार्किक छेड़छाड़ या उनका अंधाधुंध दोहन नहीं रोका गया तो नतीजे और ज्यादा व्यापक तथा भयावह होंगे। कुछ साल पहले पूर्वोत्तर में आए भूकंप के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन विभाग से जुड़े वैज्ञानिकों ने भी चेतावनी दी थी कि पहाड़ों और नदियों से छेड़छाड़ का सिलसिला रोका नहीं गया तो आने वाले समय में समूचे उत्तर भारत में भीषण तबाही मचाने वाला भूकंप आ सकता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली सहित देश के कई इलाकों में भूकंप के झटके आ भी चुके हैं।इन सारी आपदाओं और उनके मद्देनजर दी गई चेतावनियों का एक ही केंद्रीय संकेत रहा है कि हिमालय को लेकर अब हमें गंभीर हो जाना चाहिए। दुनिया के जलवायु चक्र में तेजी से हो रहे परिवर्तन के चलते हिमालय का मामला इसलिए भी बहुत ज्यादा संवेदनशील है क्योंकि यह दुनिया की ऐसी बड़ी पर्वतमाला है, जिसका अभी भी विस्तार हो रहा है। इस पर मंडराने वाला कोई भी खतरा सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि चीन, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार आदि देशों के लिए भी संकट खड़ा कर सकता है।इस खतरे की तमाम चेतावनियों और आहटों के बावजूद न तो सरकारें सचेत हैं और न ही आम लोग। दोनों की ओर से विनाशकारी विकास की गतिविधियां धड़ल्ले से जारी हैं। इस सिलसिले में मध्य हिमालयी भूभाग की कच्ची चट्टानें काटकर बनाए जा रहे विशाल बांधों के अलावा चार धाम ऑल वेदर रोड परियोजना उल्लेखनीय है, जिसका काम इस समय वहां जोर-शोर से जारी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की इस स्वप्निली परियोजना के काम की तेजी और मशीनों का शोर इतना ऊंचा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नोटिसों की फड़फड़ाहट भी किसी को सुनाई नहीं देती। यह चार हिंदू तीर्थों बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को आपस में चौड़ी और हर मौसम में खुली रहने वाली आठ लेन की सड़क से जोड़ने की परियोजना है। इस परियोजना के तहत धडल्ले से साफ किए जा रहे जंगल और पहाड़ों को काटने के लिए किए जा रहे विस्फोट ही वहां आपदा को न्योता दे रहे हैं।हिमालय पर्वतमाला को भले ही दुनिया में सबसे नई पर्वतमाला माना जाता हो, लेकिन तथ्य यह भी है कि इसी हिमालय की गोद में दुनिया की कई महान सभ्यताओं का जन्म और विकास हुआ है। कॉकेशश से लेकर भारत के पूर्वी छोर से भी आगे म्यांमार में अराका नियोमा तक सगरमाथा यानी माउंट एवरेस्ट की अगुवाई में फैली हुई विभिन्न पर्वतमालाएं हजारों वर्षों के दौरान विभिन्न सभ्यताओं के उत्थान और पतन की गवाह रही हैं। इन्हीं पर्वतमालाओं के तले सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर मोहनजोदड़ो की सभ्यता तक का जन्म हुआ। इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं की बर्फीली चट्टानों ने साईबेरिया की बर्फीली हवाओं के थपेड़ों से समूचे दक्षिण एशिया के बाशिंदों की रक्षा की और इस इलाके में दूर-दूर तक फैले हुए किसानों, वनवासियों और अन्य समूहों को फलने-फू लने में भी भरपूर मदद की।

विडंबना यह है कि जिन पर्वतमालाओं की छांह तले यह सब संभव हो पाया, आज वही पर्वतमालाएं मनुष्य की खुदगर्जी और सर्वग्रासी विकास की विनाशकारी अवधारणा की शिकार होकर पर्यावरण के गंभीर खतरे से जूझ रही हैं। इस खतरे से न सिर्फ इन पहाड़ों का बल्कि इनके गर्भ में पलने वाले प्राकृतिक ऊर्जा और जैव संपदा के असीम स्रोतों और इन पहाड़ों से निकलने वाली नदियों का अस्तित्व भी संकट में पड़ गया है। पिछले वर्षों के दौरान केदारनाथ और कश्मीर की बाढ़ तथा नेपाल और पूर्वोत्तर के भूकंप जैसी भीषण त्रासदियों और उसके बाद से लेकर अब तक जारी तमाम छोटी-बड़ी त्रासदियों की प्रकृति भले ही अलग-अलग किस्म की रही हों, लेकिन ये सभी एक तरह से हिमालय के क्षेत्र में हुई हैं और इनका एक ही संकेत है कि हिमालय को लेकर अब हमें गंभीर हो जाना चाहिए।पहाड़ी इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा देना राजस्व के अलावा स्थानीय लोगों के रोजगार की दृष्टि से जरूरी माना जा सकता है। फिर भी, इसकी आड़ में हिमालयी राज्यों की सरकारें होटल-मोटल, पिकनिक स्थल, शॉपिंग मॉल आदि विकसित करने, बिजली, खनन और दूसरी विकास परियोजनाओं और सड़कों के विस्तार के नाम पर निजी कंपनियों को मनमाने तरीके से पहाड़ों और पेड़ों को काटने की धड़ल्ले से अनुमति दे रही हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्य- सबकी दास्तानें एक जैसी दर्दनाक हैं। ये सभी इलाके कई विशिष्ट कारणों से सैलानियों के आकर्षण के केंद्र हैं, इसलिए कई निजी कंपनियों ने यहां कारोबारी गतिविधियां शुरू कर दी हैं। हालांकि स्थानीय बाशिंदे और पर्यावरण के लिए काम करने वाले स्वयंसेवी संगठन इन इलाकों में पहाड़ों और वनों की कटाई के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन सरकारी सरपरस्ती हासिल होने के कारण ये आपराधिक कारोबारी गतिविधियां निर्बाध रूप से चलती रहती हैं।

पर्यावरण संरक्षण के मकसद से ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में बाहरी लोगों के जमीन-जायदाद खरीदने पर कानूनन पाबंदी है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा राजस्व कमाने के चक्कर में इन पहाड़ी राज्यों की सरकारों के लिए इस कानून का कोई मतलब नहीं रह गया है और कई कंस्ट्रक्शन कंपनियां पहाड़ों में अपना कारोबार फैला चुकी हैं। जिन इलाकों में दो मंजिल से ज्यादा ऊंची इमारतें बनाने पर रोक थी, वहां अब बहुमंजिला आवासीय और व्यावसायिक इमारतें खड़ी हो गई हैं। बड़ी इमारतें बनाने और सड़कें चौड़ी करने के लिए जमीन को समतल बनाने के लिए विस्फोटकों के जरिए पहाड़ों की अंधाधुंध कटाई-छंटाई से पहाड़ इतने कमजोर हो गए हैं कि थोड़ी सी बारिश होने पर वे धंसने लगते हैं और पहाड़ों का जनजीवन कई-कई दिनों के लिए गड़बड़ा जाता है। पहाड़ी इलाकों में भवन निर्माण का कारोबार फैलने के साथ ही सीमेंट, बिजली आदि का उत्पादन करने वाली कंपनियों ने भी इन इलाकों में प्रवेश कर लिया है। कुछ अध्ययनों से यह भी जाहिर हो चुका है कि संचार सुविधाओं के लिए लगे टावरों से निकलने वाली तरंगों की वजह से बादलों का संतुलन बिगड़ता है और वे अचानक फटकर संकट पैदा कर देते हैं।पर्यावरण संरक्षण संबंधी कानूनों के तहत पहाड़ी और वन्य इलाकों में कोई भी औद्योगिक या विकास परियोजना शुरू करने के लिए स्थानीय पंचायतों की अनुमति जरुरी होती है, लेकिन राज्य सरकारें जमीन अधिग्रहण संबंधी अपने विशेषाधिकारों का इस्तेमाल करते हुए विकास के नाम पर आम तौर पर कंपनियों के साथ खड़ी नजर आती हैं। इन सबके खिलाफ जन-प्रतिरोध का किसी सरकार पर कोई असर नहीं होता देख अब लोगों ने अदालतों की शरण लेनी शुरू कर दी है, लेकिन अब तो अदालतें भी आमतौर पर वैसे ही फैसले देती हैं .

समाज के प्रकाश स्तम्भ होते हैं शिक्षक

रमेश सर्राफ धमोरा

हमारे देश में शिक्षकों को भगवान से भी ऊपर का दर्जा दिया गया है। इसीलिए प्रतिवर्ष शिक्षक को सम्मान देने के लिए 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के लिए रूप में मनाया जाता है। हर देश में शिक्षक दिवस को मनाने की तारीख अलग-अलग है। चीन में 10 सितम्बर तो अमेरिका में 6 मई, ऑस्ट्रेलिया में अक्तूबर का अंतिम शुक्रवार, ब्राजील में 15 अक्तूबर और पाकिस्तान में 5 अक्तूबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा ओमान, सीरिया, मिस्र, लीबिया, संयुक्त अरब अमीरात, यमन, सऊदी अरब, अल्जीरिया, मोरक्को और कई इस्लामी देशों में 28 फरवरी को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन भारत में शिक्षक दिवस को दूसरे राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में 5 सितंबर को मनाया जाता है।

शिक्षक हमें जीवन में सफलता के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल देते हैं। शिक्षक हमारे व्यक्तित्व को तैयार करते हैं। चरित्र को ढालने और मूल्यों को स्थापित करने में मदद करते हैं। हमें एक अच्छा नागरिक भी मनाने में मदद करते हैं। शिक्षक ही है जो छात्रों को जीवन का नया अर्थ सिखाता है। वे हमें सही रास्ता दिखाते हैं और कुछ भी गलत करने से रोकते हैं। वे बाहर से देख सकते हैं। वे प्रत्येक छात्र की देखभाल करते हैं और उनके विकास की कामना करते हैं। शिक्षक छात्र के व्यक्तित्व को ढालते हैं। वे एकमात्र नि:स्वार्थ व्यक्ति हैं जो खुशी-खुशी बच्चों को अपना सारा ज्ञान देते हैं। कहा जाता है कि गुरु के बिना ज्ञान अधूरा रहता है।

यह बात बिल्कुल सत्य है।

हमारे जीवन में सबसे पहली गुरु तो मां होती है जो हमें जन्म लेते ही हर बातों का ज्ञान कराती है। मगर विद्यार्थी काल में बालक के जीवन में शिक्षक ही उसे शिक्षित करता ही है और अच्छे-बुरे का ज्ञान कराता है। पहले के समय में छात्र गुरुकुल में शिक्षक के पास रहकर वर्षों विद्या अध्ययन करते थे। उस दौरान गुरु अपने शिष्यों को विद्या अध्ययन करवाने के साथ ही स्वावलंबी बनने का पाठ भी पढ़ाते थे। इसीलिए कहा गया है- गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाय, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु का स्थान ईश्वर से भी बड़ा माना गया है, क्योंकि गुरु के माध्यम से ही व्यक्ति ईश्वर को भी प्राप्त करता है।

हमारे जीवन को संवारने में शिक्षक एक बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। सफलता प्राप्ति के लिये वो हमें कई प्रकार से मदद करते है। जैसे हमारे ज्ञान, कौशल के स्तर, विश्वास आदि को बढ़ाते है तथा हमारे जीवन को सही आकार में ढ़ालते है।

कबीर दास ने शिक्षक के कार्य को इन पंक्तियो में समझाया है:-गुरु कुम्हार शिष कुंभ है, गढ़ि गढ़ि काढ़ै खोट, अंतर हाथ सहार दै, बाहर बाहै चोट

कबीर दास जी कहते हैं कि शिक्षक कुम्हार की तरह है और छात्र पानी के घड़े की तरह। जो उनके द्वारा बनाया जाता है और इसके निर्माण के दौरान वह बाहर से घड़े पर चोट करता है। इसके साथ ही सहारा देने के लिए अपना एक हाथ अंदर भी रखता है।

भारत में भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस 5 सितम्बर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को 1962 से शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने अपने छात्रों से अपने जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की इच्छा जताई थी।

डॉ राधाकृष्णन का जन्म 5 सितम्बर 1888 को तमिलनाडु के तिरुमनी गांव में हुआ था। वे बचपन से ही किताबें पढ़ने के शौकीन थे और स्वामी विवेकानंद से काफी प्रभावित थे। डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान शिक्षक थे। जिन्होंने अपने जीवन के 40 वर्ष अध्यापन पेशे को दिया है। वो विद्यार्थियों के जीवन में शिक्षकों के योगदान और भूमिका के लिये प्रसिद्ध थे। इसलिये वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने शिक्षकों के बारे में सोचा और हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रुप में मनाने का अनुरोध किया। उनका निधन 17 अप्रैल 1975 को चेन्नई में हुआ था।

वर्तमान समय में शिक्षकों का समाज में सम्मान कम होने लगा है। बहुत से शिक्षकों की घटिया हरकतों ने उनको समाज की नजरों से गिरा दिया है। स्कूल, कालेजों में छात्र, छात्राओं के साथ शिक्षकों द्वारा नीच हरकते करने के चलते शिक्षण जैसा पवित्र कार्य बदनाम होता जा रहा है। मौजूदा दौर में शिष्य भी कुछ कम नहीं हैं। छात्रों की अनुशासनहीनता के चलते स्कूल, कालेजों में शिक्षा का वातावरण समाप्त होता जा रहा है। गुरू-शिष्य को एक-दूसरे की भावनाओं को समझ कर मिलजुल कर ज्ञान की ज्योति जलानी होगी। शिक्षक दिवस मनाने के साथ हमें शिक्षण कार्य की पवित्रता को फिर से बहाल करने की प्रतिज्ञा भी लेनी होगी। तभी हमारा शिक्षक दिवस मनाना सार्थक हो पायेगा।

(लेखक, हिन्दुस्थान समाचार से संबद्ध हैं।)

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना देगी युवा शक्ति के सपनों को नई उड़ान

डॉ. मनसुख मांडविया

भारत की विकास गाथा हमेशा से उसकी श्रम शक्ति द्वारा लिखी गई है। देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में करोड़ों श्रमिकों के समर्पण और क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, पिछले 11 वर्षों में भारत की आर्थिक प्रगति ने उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्ष 2014 में, भारत विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ते हुए आज चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।

भारत ने वैश्विक पटल पर अपने लिए एक उल्लेखनीय स्थान बनाया है और इसमें इसके मानव संसाधन की शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस सफलता की कहानी को बल देने वाला तथ्य यह है कि भारत के आर्थिक विकास के साथ-साथ रोजगार का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। आरबीआई-केएलईएमएस के अनुसार, जहां 2004-2014 के बीच केवल 2.9 करोड़ रोजगार सृजित हुए थे, उसके बाद के दशक में 17 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित हुए। औपचारिकीकरण में भी तेजी आई है, ईपीएफओ के आंकड़ों के अनुसार पिछले सात वर्षों में लगभग आठ करोड़ नौकरियां सृजित हुई हैं।

भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज में बढ़तोरी होना भी हमारी एक बड़ी उपलब्धि है। 2015 में, केवल 19 प्रतिशत भारतीय कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत आते थे। 2025 तक, यह संख्या बढ़कर 64.3 प्रतिशत हो चुकी है और 94 करोड़ लाभार्थी इसके दायरे में आए हैं, जिससे भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा कवरेज देने वाला देश बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने इस उपलब्धि को वैश्विक स्तर पर कवरेज के सबसे तेज विस्तार में से एक माना है। यह स्पष्ट है कि राष्ट्र का भविष्य न केवल जीडीपी वृद्धि की गति से, बल्कि हमारे द्वारा सृजित नौकरियों की गुणवत्ता, श्रमिकों को दी जाने वाली सुरक्षा और अपने युवाओं को प्रदान किए जाने वाले अवसरों से भी तय होगा। बढ़ते स्वचालन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कारण बनी अनिश्चितता की स्थिति, आपूर्ति-श्रृंखला में बदलाव और दुनिया भर में नौकरियों को आकार देने वाली कई अन्य कमजोरियों की वैश्विक पृष्ठभूमि में, भारत एक जनसांख्यिकीय परिवर्तन के बिंदु पर खड़ा है।

हमारी 65 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है, जो एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय लाभांश है जो हमारी अर्थव्यवस्था को गति दे देता है, जबकि पश्चिमी देशों में आबादी वृद्ध होती हो रही है। वर्षों से, भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश यानी इसकी युवा शक्ति को इसकी सबसे बड़ी ताकत माना जाता रहा है। फिर भी, पिछली सरकारों के अधीन, इस क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया गया।

इस पृष्ठभूमि में, रोजगार अब केवल एक आर्थिक संकेतक नहीं रह गया है; यह सम्मान, समानता और राष्ट्रीय शक्ति का आधार है। इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने युवाओं को रोजगार योग्य बनाएं, उन्हें औपचारिक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करें, उन्हें वित्तीय साक्षरता से लैस करें और यह सुनिश्चित करें कि वे एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली द्वारा सुरक्षित हों। तभी हमारा जनसांख्यिकीय लाभ वास्तव में एक स्थायी राष्ट्रीय लाभांश में परिवर्तित हो सकता है। इसी चुनौती का समाधान करने और आकांक्षा व अवसर के बीच के अंतर को पाटने के लिए, 15 अगस्त को लाल क़िले की प्राचीर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है।

शुरुआत में केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रस्तुत और प्रधानमंत्री जी के अपने 12वें स्वतंत्रता दिवस संबोधन में घोषित यह योजना पैमाने और डिजाइन, दोनों ही दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है। 1 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ, यह भारत के इतिहास का सबसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जिससे 3.5 करोड़ से ज्यादा रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। इनमें से दो करोड़ लाभार्थी पहली बार नौकरी पाने वाले होंगे। योजना के दो स्तंभ- पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन और नियोक्ताओं को सहायता प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को इसकी संरचना ही अलग बनाती है। रोजगार सृजन को बढ़ावा देने वाले पहले के कार्यक्रमों के विपरीत, यह योजना युवाओं की रोजगार क्षमता और उद्यम प्रतिस्पर्धात्मकता की दोहरी चुनौती का एक साथ समाधान करती है। भाग 'ए' के तहत पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों (दो किश्तों में 15,000 रुपए तक) और भाग 'बी' के तहत नियोक्ताओं (प्रत्येक नए कर्मचारी के लिए प्रति माह 3,000 रुपए तक) को प्रत्यक्ष वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके, यह श्रमिकों के लिए प्रवेश बाधाओं को कम करता है और साथ ही व्यवसायों के लिए नियुक्ति जोखिम को भी कम करता है। इस योजना का औपचारिकीकरण और सामाजिक सुरक्षा एकीकरण की दिशा में प्रोत्साहन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसके लाभ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और नए कर्मचारियों को पहले दिन से ही सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों से जोड़ा जा सकेगा। इस प्रकार, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, एक औपचारिक, सुरक्षित और उत्पादक श्रम बाजार की ओर एक संरचनात्मक कदम है। इसके अलावा, विनिर्माण क्षेत्र में नियोक्ताओं को प्रोत्साहन पर अतिरिक्त ध्यान, भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और प्रयास है। समावेशी और सतत विकास को गति देना प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, योजना-आधारित पहलों से हटकर एक व्यापक रोजगार प्रणाली की ओर बदलाव का संकेत देती है। यह पूर्व की पहलों से मिली सीख पर आधारित है, उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई), राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन और मेक इन इंडिया जैसी वर्तमान योजनाओं का पूरक है और प्रतिस्पर्धी वैश्विक व्यवस्था में काम की बदलती प्रकृति को पहचानती है। श्रमिकों और नियोक्ताओं, दोनों को प्रोत्साहन देकर, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना यह मान्यता देती है कि रोजगार सृजन एक साझा जिम्मेदारी है। भारत डिजिटल नवाचार को अपनाते हुए एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने का प्रयास कर रहा है, इसलिए यह योजना सुनिश्चित करती है कि कोई भी पीछे न छूटे - यहां तक कि सबसे छोटा उद्यम और कार्यबल में शामिल होने वाला सबसे नया व्यक्ति भी राष्ट्रीय विकास की यात्रा में भागीदार बने। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना- नए भारत की नींव प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना एक नीतिगत घोषणा से कहीं अधिक बढ़कर है। यह जनसांख्यिकीय लाभांश को सार्वजनिक समृद्धि में बदलने की दिशा में एक ठोस कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, यह पहल विकसित भारत के विजन को साकार करने की नींव का हिस्सा है, जहां हर युवा को

सार्थक रोजगार मिले, हर काम में सम्मान हो और हर युवा को अपने सपनों को साकार करने का अवसर मिले।

रोजगार निर्माण सही मायने में राष्ट्र निर्माण है। इस पहल के साथ, मोदी सरकार अपनी इस प्रतिबद्धता के साथ

आगे बढ़ रही है कि कोई भी आकांक्षा अधूरी नहीं रहेगी और कोई भी युवा अवसर से वंचित नहीं रहेगा। हम

सब मिलकर भारत की युवा शक्ति को नई उड़ान दे रहे हैं और उनके माध्यम से, विकसित भारत के सपने को भी

नई गति प्रदान कर रहे हैं।

***

डॉ. मनसुख मांडविया

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री, भारत सरकार

यूएस ओपनः पुरुष युगल के क्वार्टरफाइनल में पहुंचे युकी भांबरी

एजेंसी

नई दिल्ली। भारतीय टेनिस खिलाड़ी युकी भांबरी ने अपने करियर में पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के क्वार्टरफाइनल में जगह बनाई है। वे न्यूज़ीलैंड के साथी माइकल वीनस के साथ मिलकर यूएस ओपन के पुरुष युगल स्पर्धा में क्वार्टरफाइनल दौर में पहुंचे हैं। पुरुष युगल स्पर्धा में 14वीं वरीयता प्राप्त इस जोड़ी ने चौथी वरीयता प्राप्त जर्मन जोड़ी केविन क्राविएट्ज़ और टिम पुत्ज़ को सीधे सेटों में 6-4, 6-4 से हराया। अब गुरुवार को इस जोड़ी का सामना 11वीं वरीयता प्राप्त क्रोएशिया के निकोला मेक्टिक और अमेरिकी दिग्गज राजीव राम की जोड़ी से होगा। 33 वर्षीय युकी इस सीज़न में ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने रॉबर्ट गैलोवे के साथ मिलकर फ्रेंच ओपन और विंबलडन में तीसरे दौर तक जगह बनाई थी। मियामी ओपन 2025 के बाद युकी देश के नंबर 1 डबल्स खिलाड़ी बने थे, जहां उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए रोहन बोपन्ना को पीछे छोड़ा था। युकी वर्तमान में एटीपी डबल्स रैंकिंग में 32वें स्थान पर हैं, जबकि लाइव रैंकिंगमें वे 28वें नंबर पर पहुंच गए हैं। युकी का हालिया प्रदर्शन शानदार रहा है और इसी कड़ी में मार्च 2025 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के एलेक्सी पोपायरिन के साथ मिलकर दुबई टेनिस चैंपियनशिप जीतकर अपना पहला एटीपी 500 खिताब हासिल किया था।

दलीप ट्रॉफीः एशिया कप का स्टैंडबाय खिलाड़ी सेमीफाइनल में पहले ओवर में आउट, बनाए केवल 4 रन

नई दिल्ली। भारत के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल वेस्ट जोन और सेंट्रल जोन के बीच दलीप ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल मुकाबले में जल्दी आउट हो गए। जायसवाल को टी20 विश्व कप 2025 के लिए चयनकर्ताओं द्वारा नजरअंदाज किया गया और उन्हें स्टैंडबाय खिलाड़ियों में रखा गया। इंग्लैंड की धरती पर एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 के बाद जायसवाल अपने पहले मैच में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सके। वेस्ट जोन के कप्तान शार्दुल ठाकुर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया जिसके बाद जायसवाल ने हार्विक देसाई के साथ पारी की शुरुआत करने उतरे। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज खलील अहमद द्वारा फेंके गए पहले ओवर की तीसरी गेंद पर जायसवाल एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। अपना विकेट गंवाने से पहले जायसवाल ने तीन गेंदों में एक चौका लगाया। जायसवाल के सलामी जोडीदार देसाई भी नई गेंद का सामना नहीं कर सके। उन्होंने चार गेंदों पर सिर्फ एक रन बनाकर चौथे ओवर में दीपक चाहर का शिकार होकर अपना विकेट गंवा दिया। शुरुआती दो विकेट गिरने के बाद आर्य देसाई और रुतुराज गायकवाड़ ने पारी को संभाला। उन्होंने अहमद और चाहर की नई गेंदों का अच्छी तरह सामना किया।

रोहित और विराट के 2027 विश्व कप में खेलने पर बोले आकाश चोपड़ा, यह भी बहुत दूर की बात है लेकिन...

नई दिल्ली। विराट कोहली और रोहित शर्मा के 2027 विश्व कप को लेकर बहुत सी अटकलें लगाई जा रही हैं जिसमें उनका टीम में ना होना भी शामिल। लेकिन इन सवालिया निशानों के बीच पूर्व क्रिकेटर और मौजूदा कमेंटेटर आकाश चोपड़ा को लगता है कि दोनों के पास एक और बार खेलने के लिए कौशल और फिटनेस दोनों हैं। चोपड़ा ने कहा, दोनों विश्व कप तक खेल सकते हैं। चूंकि 2027 विश्व कप दक्षिण अफ्रीका में है, इसलिए अनुभव और कौशल की आवश्यकता होगी। फिर से, यह भी बहुत दूर की बात है, लेकिन दोनों के पास 2027 विश्व कप तक खेलने की वास्तविक संभावनाएं हैं। हालांकि, वे कम क्रिकेट खेल रहे हैं, और मुझे यह पसंद नहीं है। टेस्ट और टी20 मैच न खेलने का मतलब है कि विराट और रोहित अब बहुत कम खेलेंगे। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि उन्हें ज्यादा क्रिकेट खेलना चाहिए था। अगर वे टेस्ट खेलते रहते, तो वे काफी क्रिकेट खेलते। मुझे नहीं पता कि उन्होंने टेस्ट क्यों छोड़ दिया और वनडे क्यों खेल रहे हैं, और टी20 भी क्यों छोड़ दिया। दो महीने का IPL और फिर 10 महीनों में 10 मैच। निजी तौर पर, मुझे यह समझ नहीं आता।

इरफान पठान ने एशिया कप के लिए इस भारतीय को बताया एक्स-फैक्टर, टी20 में शानदार आंकड़े

नई दिल्ली। भारत के पूर्व स्टार गेंदबाज इरफान पठान ने 9 सितंबर से शुरू होने वाले एशिया कप 2025 के लिए वरुण चक्रवर्ती को भारतीय टीम का एक्स-फैक्टर चुना। क्रिकेट विशेषज्ञ अक्सर हार्दिक पांड्या या जसप्रीत बुमराह को खेल परिवर्तक खिलाड़ी के रूप में चुनते है लेकिन इरफान ने मिस्ट्री स्पिनर वरुण को भारतीय टीम का एक्स-फैक्टर बताया। पठान ने सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर कहा, 'मैं यह देखने के लिए उत्सुक हूं कि वरुण चक्रवर्ती कैसा प्रदर्शन करते है क्योंकि यह उनके लिए एक तरह से वापसी की कहानी होगी। वह यूएई में हुए 2021 विश्व कप में थे और उन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। इसलिए मेरी नजर उन पर होगी क्योंकि वह अभी अच्छी फॉर्म में है और आत्मविश्वास से भरे है। इसलिए सभी नामों में से एक को चुनने के लिए मैं वरुण को चुनूंगा।' एशिया कप 2025 के लिए भारतीय गेंदबाजी आक्रमण का चयन करते हुए पठान ने कहा, 'अंतिम संयोजन पिचों और ओस के प्रकार पर निर्भर करेगा लेकिन मैं बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और अभिषेक शर्मा को चुनूंगा।'

सीपीएल 2025 : सेंट लूसिया किंग्स ने त्रिनबागो नाइट राइडर्स को 7 विकेट से रौंदा, प्लेऑफ में बनाई जगह

एजेंसी

नई दिल्ली। त्रिनिदाद में खेले गए मुकाबले में (भारतीय समयानुसार गुरुवार) सेंट लूसिया किंग्स ने हाई-फ्लाइंग त्रिनबागो नाइट राइडर्स को 53 गेंदें शेष रहते 7 विकेट से मात दी। इस जीत के साथ किंग्स नाइट राइडर्स के बाद सीपीएल 2025 प्लेऑफ में क्वालीफाई करने वाली दूसरी टीम बन गई। किंग्स की जीत में उनके स्पिन गेंदबाजों का अहम योगदान रहा। तबरेज़ शम्सी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट झटके, वहीं खारी पियरे और रोस्टन चेज़ ने 2-2 विकेट लेकर विपक्षी बल्लेबाज़ों की कमर तोड़ दी। मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी करने उतरी नाइट राइडर्स की शुरुआत बेहद खराब रही। कोलिन मुनरो दूसरे ही गेंद पर पियरे का शिकार बने। डैरेन ब्रावो ने कुछ बड़े शॉट्स लगाए लेकिन जल्द ही

आउट हो गए। निकोलस पूरन ने भाग्य का सहारा लेते हुए शुरुआत में बचाव पाया और उसके बाद लगातार दो छक्के जड़े, मगर टीकेआर का पतन जारी रहा। एलेक्स हेल्स पावरप्ले की अंतिम गेंद पर आउट हुए और 6 ओवर की समाप्ति पर टीम 3 विकेट खो चुकी थी। इसके बाद शम्सी ने आते ही अकील होसैन को पहली ही गेंद पर पवेलियन भेजा। पूरन भी ज्यादा देर टिक नहीं सके और चेज़ की गेंद पर विकेटकीपर को कैच थमा बैठे। आंद्रे रसेल को शम्सी ने बोल्ड कर नाइट राइडर्स की उम्मीदों को करारा झटका दिया। पोलार्ड भी शम्सी के शिकार बने। अंत में टेरेंस हाइंड्स और नाथन एडवर्ड्स ने टीम को 100 के पार पहुंचाया लेकिन पोटगीटर और अल्जारी जोसेफ ने आखिरी झटके दिए और पूरी टीम 109 पर ढेर हो गई। लक्ष्य का पीछा करते हुए टिम सीफर्ट ने धमाकेदार शुरुआत की। उन्होंने पहले ही ओवर में 14 रन ठोक डाले और तेजी से रन बटोरे। जॉनसन चार्ल्स जल्दी आउट हो गए, लेकिन सीफर्ट और अकीम ऑगस्टे ने मिलकर 40 रन की साझेदारी की। ऑगस्टे ने रसेल की गेंदों पर ताबड़तोड़ प्रहार करते हुए 20 रन लूटे। सीफर्ट 36 रन बनाकर आउट हुए जबकि ऑगस्टे ने भी 28 रन की तेज पारी खेली।

पुनेरी पल्टन की जीत की हैट्रिक, बंगाल वारियर्स को दी पहली हार

एजेंसी

विशाखापट्टनम। प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) सीजन-12 में पुनेरी पल्टन का विजयी अभियान जारी है। विश्वनाथ स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम में खेले गए 11वें मैच में पल्टन ने बंगाल वारियर्स को 45-36 से हराते हुए लगातार तीसरी जीत दर्ज की। इस हार के साथ बंगाल का अपराजेय क्रम भी टूट गया।पल्टन की जीत में कप्तान असलम इनामदार और आदित्य शिंदे चमके, दोनों ने 10-10 अंक हासिल किए। डिफेंस में विशाल भारद्वाज ने हाई-5 लगाया, जबकि गुरदीप और पंकज मोहिते ने 5-5 अंक जुटाए। दूसरी ओर बंगाल के लिए देवांक दलाल ने अकेले दम पर शानदार प्रदर्शन किया और 17 अंक अर्जित किए, लेकिन साथियों का समर्थन न मिलने से टीम हार से नहीं बच सकी। मैच की शुरुआत कड़ी टक्कर से हुई और शुरुआती 10 मिनट तक दोनों टीमें बराबरी पर रहीं। इसके बाद पुनेरी ने लय पकड़ी और पहले हाफ में 26-22 की बढ़त बना ली। हाफटाइम तक असलम और देवांक ने सुपर-10 पूरा किया।

दूसरे हाफ में पुनेरी ने और आक्रामक खेल दिखाया और बंगाल को आलआउट कर 34-24 की मजबूत बढ़त ले ली। देवांक ने बोनस प्वाइंट्स लेकर अंतर कम करने की कोशिश की, लेकिन आदित्य और पंकज के लगातार रेड ने पल्टन को बढ़त बनाए रखा अंतिम 10 मिनट में बंगाल ने वापसी की कोशिश जरूर की, मगर गुरदीप की शानदार टैकलिंग ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अंततः पुनेरी पल्टन ने 9 अंकों से मैच अपने नाम कर सीजन की जीत की हैट्रिक पूरी कर ली।

लखनऊ फाल्कन्स ने एलिमिनेटर में गोरखपुर लायंस को हराया, सेमीफाइनल में बनाई जगह

एजेंसी

लखनऊ। यूपी टी20 लीग सीजन-3 के एलिमिनेटर मुकाबले में लखनऊ फाल्कन्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोरखपुर लायंस को 23 रन से हराकर सेमीफाइनल का टिकट पक्का कर लिया। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में फाल्कन्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 170 रन बनाए। जवाब में गोरखपुर की टीम 8 विकेट खोकर केवल 147 रन ही बना सकी। फाल्कन्स के लिए अभय चौहान (33 रन, 21 गेंद, 4 छक्के) और मो. सैफ (32 रन, 22 गेंद) ने आतिशी पारी खेली। इसके अलावा अंश यादव (28), समीर चौधरी (21) ने उपयोगी योगदान दिया। आख़िरी ओवरों में सत्याम पांडे (24, 12 गेंद, 2 छक्के)* और विप्रज निगम (13, 6 गेंद, 1 छक्का)* ने तेजी से रन जोड़कर टीम को 170 तक पहुंचाया। गोरखपुर के लिए अब्दुल रहमान और प्रिंस यादव ने 2-2 विकेट लिए।

लक्ष्य का पीछा करते हुए गोरखपुर की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही।

टीम ने पहले ही ओवर में विकेट गंवा दिया। हालांकि, निशांत कुशवाह (34 रन) और कप्तान आक्षदीप नाथ (15 रन) ने थोड़ी साझेदारी निभाई। इसके बाद सिद्धार्थ यादव (50 रन, 41 गेंद, 5 चौके, 1 छक्का) ने जुझारू अर्धशतक जमाया लेकिन बाकी बल्लेबाज़ उनका साथ नहीं दे सके। आख़िरी ओवरों में विकेट लगातार गिरते रहे और पूरी टीम 147/8 तक ही सिमट गई। फाल्कन्स के कप्तान भुवनेश्वर कुमार ने अपने अनुभव का शानदार प्रदर्शन किया और 4 ओवर में 26 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट झटके। नवनीत कुमार (3/33) और अक्षु बाजवा (2/29) ने भी बेहतरीन गेंदबाज़ी की। वहीं, विप्रज निगम को 1 सफलता मिली। इस जीत के साथ लखनऊ फाल्कन्स ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है जबकि गोरखपुर लायंस का सफर यहीं समाप्त हो गया।

हीरो पुरुष एशिया कप 2025 : भारत ने सुपर 4 के पहले मुकाबले में कोरिया को 2-2 से बराबरी पर रोका

एजेंसी

राजगीर (बिहार)। हीरो मेन्स एशिया कप हॉकी 2025 के सुपर-4 चरण के पहले मुकाबले में भारत और कोरिया के बीच रोमांचक 2-2 की बराबरी देखने को मिली। भारत की ओर से हार्दिक सिंह (8') और मंदीप सिंह (53') ने गोल दागे, जबकि कोरिया के लिए जिहुन यांग (12') और ह्योनहोंग किम (14') ने गोल किए।बारिश के कारण मैच की शुरुआत थोड़ी देर से हुई, लेकिन भारत ने तेज रफ्तार से खेल की शुरुआत की।

8वें मिनट में सुखजीत सिंह की मदद से हार्दिक ने शानदार सोलो रन लेते हुए गोलकीपर को चकमा देकर पहला गोल दागा। हालांकि, कोरिया ने तुरंत वापसी की। 12वें मिनट में जुगराज सिंह की गलती पर पेनल्टी स्ट्रोक मिला जिसे जिहुन यांग ने गोल में बदला। इसके दो मिनट बाद पेनल्टी कॉर्नर पर ह्योनहोंग किम ने दमदार ड्रैगफ्लिक के जरिए स्कोर 2-1 कर दिया दूसरे क्वार्टर में भारतीय

टीम ने लगातार अटैक किया लेकिन कोरियाई डिफेंस मजबूत रहा। कप्तान हरमनप्रीत सिंह और जारमनप्रीत ने मौके बनाए लेकिन गोलकीपर को भेद नहीं सके। तीसरे क्वार्टर में भी भारत ने कई मौकों को गंवाया। मनप्रीत और अभिषेक की कोशिशें नाकाम रहीं, वहीं हरमनप्रीत का ड्रैगफ्लिक भी डिफेंडर ने गोललाइन पर रोक लिया।चौथे क्वार्टर में भारत ने जोरदार दबाव बनाया। 49वें मिनट में जुगराज का पेनल्टी कॉर्नर नाकाम रहा, लेकिन 53वें मिनट में सुखजीत सिंह ने शानदार पास देकर मंदीप सिंह को गोल का मौका दिया, जिसे उन्होंने बखूबी भुनाया और स्कोर 2-2 कर दिया। अंतिम मिनटों में दोनों टीमों को पेनल्टी कॉर्नर मिले, मगर गोल नहीं हो सका और मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ।

एशिया कप से पहलेलगातार तीसरे टी20 सीरीज जीत से उत्साहित हैं लिटन दास

एजेंसी

ढाका। बांग्लादेश टी20 टीम के कप्तान लिटन कुमार दास ने कहा है कि उनकी टीम आगामी एशिया कप के लिए पूरी तरह तैयार है। टूर्नामेंट का आगाज़ 9 सितंबर से यूएई में होने जा रहा है। बांग्लादेश ने हाल ही में नीदरलैंड्स को तीन मैचों की टी20 सीरीज में 2-0 से हराया। तीसरा मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया। यह बांग्लादेश की लगातार तीसरी टी20 सीरीज जीत है। इससे पहले उन्होंने श्रीलंका और पाकिस्तान को हराया था लिटन ने टीम की इस सफलता का श्रेय प्री-सीरीज कैंप को दिया। टीम ने पहले ढाका में फिटनेस कैंप लगाया और फिर सिलहट में स्किल कैंप आयोजित किया, जहां बेहतर पिचों पर खिलाड़ियों ने अभ्यास किया। लिटन ने कहा, मुझे लगता है हम एशिया कप के लिए अच्छी तरह तैयार हैं। जो कैंप हमने किया था, वह

सिर्फ इस सीरीज के लिए नहीं था, बल्कि एशिया कप को ध्यान में रखकर किया गया था। मैंने पहले कभी इतना अच्छा कैंप नहीं देखा। उन्होंने आगे कहा, फिटनेस तो मीरपुर में भी हो सकती थी, लेकिन जिस तरह की प्रैक्टिस की ज़रूरत थी, वह केवल सिलहट में संभव थी। कुल मिलाकर यह यात्रा हमारे लिए बहुत फायदेमंद रही। लिटन ने इस दौरान खिलाड़ियों को मिले मैच टाइम को भी अहम बताया। जिसे भी खेलने का मौका मिला, उसने अच्छा प्रदर्शन किया। सिर्फ सैफुद्दीन ही कुछ खास नहीं कर पाए। बाकियों ने कम से कम एक मैच में योगदान दिया। प्रैक्टिस जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है मैच में प्रदर्शन करना। मैच खेलने से ही खेल का अनुभव और समझ बढ़ती है।उन्होंने माना कि सभी बल्लेबाज़ों को मौके नहीं मिल पाए, लेकिन इसे सकारात्मक संकेत बताया। ÷यह अच्छी बात है कि हमारे टॉप ऑर्डर ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि मिडिल ऑर्डर को मौका ही नहीं मिला। एशिया कप में वह दिन भी आएगा जब हर किसी को बल्लेबाज़ी करनी होगी, लेकिन फिलहाल यह हमारे लिए सकारात्मक संकेत है। बांग्लादेश अपना एशिया कप अभियान 11 सितंबर को हांगकांग के खिलाफ शुरू करेगा।

आईओए और आईओसी की साझेदारी बहाल, अब खिलाड़ियों को मिलेगा सीधा फायदा

एजेंसी

नई दिल्ली। भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) ने अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) के साथ साझेदारी के दोबारा शुरू होने और ओलंपिक सॉलिडेरिटी कार्यक्रमों की बहाली का स्वागत किया है। यह उपलब्धि भारतीय खेलों में हाल ही में हुए महत्वपूर्ण शासन सुधारों और प्रगति का प्रतीक मानी जा रही है। आईओसी ने आईओए अध्यक्ष को भेजे एक पत्र में संघ और भारत सरकार के उठाए गए सकारात्मक कदमों की सराहना की, जिनका उद्देश्य जमीनी स्तर से लेकर एलीट स्तर तक खिलाड़ियों को सहयोग और समर्थन प्रदान करना है। आईओसी ने आईओए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीइओ) के रूप में रघुराम अय्यर की औपचारिक नियुक्ति और राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम (नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट) अपनाने को भारतीय खेल व्यवस्था की नींव मजबूत करने के लिए अहम माना है। ओलंपिक सॉलिडेरिटी कार्यक्रमों की बहाली से भारत के खिलाड़ियों को सीधा लाभ मिलेगा। इस पहल से खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, तैयारी और ओलंपिक खेलों सहित अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी के लिए प्रत्यक्ष फंडिंग और विकास के अवसर उपलब्ध होंगे। आईओए अध्यक्ष डॉ. पी.टी. उषा ने इस घोषणा को भारतीय खेलों के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने कहा, ÷यह आईओए और भारत सरकार के साझा संकल्प को दर्शाता है कि नई और परिवर्तनकारी खेल नीति के तहत खेल शासन में उच्चतम मानकों को बनाए रखा जाए। आईओसी के साथ यह नई साझेदारी हमारे खिलाड़ियों को उनके ओलंपिक सपनों को साकार करने में बड़ी भूमिका निभाएगी। भारतीय ओलंपिक संघ ने आश्वासन दिया है कि वह आईओसी के साथ मिलकर भारत में ओलंपिक आंदोलन को और सशक्त बनाने और खिलाड़ियों को सतत समर्थन देने की दिशा में काम करता रहेगा।

भारत के सुकांत कदम एसएल4 पैरा बैडमिंटन श्रेणी में बने विश्व के नंबर एक खिलाड़ी

एजेंसी

नई दिल्ली। भारतीय पैरा बैडमिंटन स्टार सुकांत कदम ने एसएल 4 कैटेगरी में वर्ल्ड नंबर-1 रैंकिंग हासिल कर नया इतिहास रच दिया है। यह पहली बार है, जब वे वैश्विक रैंकिंग के शीर्ष पर पहुंचे हैं। सुकांत ने पिछले कुछ वर्षों में वर्ल्ड पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप और एशियन पैरा गेम्स में कई पदक जीते हैं। हाल ही में उन्होंने स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2025 में स्वर्ण पदक जीतकर अपनी रैंकिंग और आत्मविश्वास को और मजबूती दी। अब उनका अगला लक्ष्य चाइना पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2025 है, जहां वे अपनी वर्ल्ड नंबर-1 स्थिति बरकरार रखने और 2026 एशियन गेम्स के लिए तैयारी करने उतरेंगेअपनी सफलता पर खुशी

जताते हुए सुकांत कदम ने कहा, 'वर्ल्ड नंबर-1 बनना मेरे लिए किसी सपने के पूरे होने जैसा है। यह मुझे रोजाना और मेहनत करने की प्रेरणा देता है। मेरा ध्यान अब चाइना पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल और अगले साल एशियन गेम्स पर है, जहां मैं भारत के लिए गोल्ड जीतना चाहता हूं।' उन्होंने आगे कहा, मैं चाहता हूं कि मेरी यह उपलब्धि भारत को गर्व महसूस कराए और आने वाली पीढ़ी के पैरा एथलीट्स को प्रेरित करे। मैं अपने कोच निखिल कानेतकर और मयंक गोले का आभारी हूं, जिन्होंने हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया। साथ ही अपनी टीम को भी धन्यवाद, जो इस सफर में मेरे साथ खड़ी रही। जुलाई, 2025 में सुकांत ने ब्रिटिश और आयरिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में भी शानदार प्रदर्शन किया था। एसएल4 कैटेगरी के सेमीफाइनल में उन्होंने भारत के नवीन शिवकुमार को सीधे सेटों में हराया। हालांकि फाइनल में वे फ्रांस के पैरा ओलंपिक चैंपियन लुकास माजुर से कड़े मुकाबले में हारकर रजत पदक पर सिमट गए।

दक्षिण अफ्रीका ने वर्ल्ड कप के लिए घोषित की टीम, वैन नीकेर्क बाहर

एजेंसी

नई दिल्ली। दक्षिण अफ्रीका की पूर्व कप्तान डेन वैन नीकेर्क को महिला वर्ल्ड कप की टीम में जगह नहीं मिली है। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका (सीएसए) ने 15 सदस्यीय मजबूत टीम का ऐलान किया। वैन नीकेर्क ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय संन्यास से वापसी की थी और तैयारी कैंप के लिए 20 सदस्यीय स्क्वॉड में शामिल थीं, लेकिन आखिरकार अंतिम चयन से बाहर हो गईं। टीम की कमान लॉरा लौरा वोल्वार्ड्ट संभालेंगी। उनके साथ क्लोई ट्रायन, मरिजाने कप्प, सुने लूस और आयाबोंगा खाका जैसी अनुभवी खिलाड़ी टीम में शामिल हैं। विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी साइनलो जाफ्टा और कराबो मेसो निभाएंगी। खास बात यह है कि कराबो मेसो पहली बार सीनियर वर्ल्ड कप खेलेंगी। युवा ऑलराउंडर मियाने स्मिट को ट्रैवलिंग रिजर्व के रूप में चुना गया है। वे पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप में भी इसी भूमिका में थीं।

टूर्नामेंट से पहले दक्षिण अफ्रीका की टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी और वहां तीन वनडे खेलेगी। इसके बाद टीम 3 अक्टूबर को इंग्लैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत करेगी। इसके अलावा वे न्यूजीलैंड, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया से भी भिड़ेंगी। हेड कोच मांडला मशिंबयी ने कहा, जब से मैंने इस टीम के साथ काम करना शुरू किया, हमारा लक्ष्य वर्ल्ड कप के लिए मजबूत तैयारी करना रहा है। हमें भरोसा है कि यह टीम दक्षिण अफ्रीका को गर्व महसूस कराएगी। अब बस जरूरत है इस विश्वास को हर कदम पर बनाए रखने की।

दक्षिण अफ्रीका की टीम

लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), आयाबोंगा खाका, क्लोई ट्रायन, नादिन डी क्लर्क, मरिजाने कप्प, ताजमिन ब्रिट्स, साइनलो जाफ्टा, नोंकुलुलेको मलाबा, एनेरी डेरक्सन, एनेके बॉश, मसाबाता क्लास, सुने लूस, कराबो मेसो, तूमी सेखुखुने, नोंडुमिसो शांगासे।

ब्रायन बेनेट ने T20I क्रिकेट में खेली शानदार पारी, फाफ डू प्लेसिस और बाबर आजम का अनोखा रिकॉर्ड तोड़ा

एजेंसी

हरारे। जिम्बाब्वे के सलामी बल्लेबाज ब्रायन बेनेट ने हरारे में एक अनोखा बल्लेबाजी कमाल करके रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया जबकि उनकी टीम तीन मैचों की सीरीज के पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में श्रीलंका से चार विकेट से हार गई। 57 गेंदों में 81 रनों की तेज पारी खेलने वाले बेनेट आईसीसी के पूर्ण सदस्यों में बिना छक्का लगाए सर्वोच्च टी20आई स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। बेनेट की 12 चौकों से सजी पारी ने हरारे स्पोर्ट्स क्लब में जिम्बाब्वे के 175-7 के स्कोर तक पहुंचने में मदद की। लेकिन उनकी इस पारी के बावजूद मेजबान टीम श्रीलंका को 5 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल करने से नहीं रोक सकी। 27 वर्षीय दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने फाफ डु प्लेसिस (79* बनाम बांग्लादेश, 2015) और बाबर आजम (79 बनाम न्यूजीलैंड) के संयुक्त रूप से पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। इस अनूठी सूची में अन्य उल्लेखनीय नाम मोहम्मद रिजवान (78 बनाम वेस्टइंडीज) और रिकी पोंटिंग (76 बनाम भारत) हैं। हालांकि सभी आईसीसी सदस्यों के बीच सर्वकालिक रिकॉर्ड मलावी के सामी सोहेल के नाम है जिन्होंने 2022 में लेसोथो के खिलाफ बिना पिचिंग किए नाबाद 94 रन बनाए थे।

सिकंदर रजा पहली बार बने एकदिवसीय क्रिकेट के शीर्ष ऑलराउंडर

एजेंसी

दुबई। हरारे में श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की श्रृंखला में शानदार प्रदर्शन वाले जिम्बाब्वे के स्टार खिलाड़ी सिकंदर रजा अपने करियर में पहली बार आईसीसी पुरुष एकदिवसीय खिलाड़ी ऑलराउंडर रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंच गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर केशव महाराज गेंदबाजी रैंकिंग में नंबर वन पर है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की ओर से जारी रैंकिंग की ताजा अपडेट के अनुसार 39 वर्षीय रजा ने दोनों मैचों में 92 और नाबाद 59 रन बनाए और श्रृंखला में एक विकेट लेकर अफगानिस्तान के अजमतुल्लाह ओमरजई और मोहम्मद नबी को पछाड़ते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया। वहीं ओमरजई दूसरे और नबी तीसरे स्थान पर हैं। रजा का पिछला सर्वश्रेष्ठ दूसरा स्थान था जो उन्होंने दिसंबर 2023 में हासिल किया था। रजा के कुल 151 रन ने उन्हें बल्लेबाजी रैंकिंग में नौ पायदान ऊपर चढ़कर 22वें स्थान पर पहुंच गये है जो कि जून 2023 में उनके करियर के सर्वश्रेष्ठ 24वें स्थान से दो पायदान नीचे है। गेंदबाजों में भी वह एक पायदान ऊपर चढ़कर 38वें स्थान पर पहुंच गए हैं। श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज पथुम निसंका सात स्थान ऊपर चढ़कर 13वें स्थान पर पहुंच गए हैं, श्रीलंका के ही जनिथ लियानागे (13 स्थान ऊपर चढ़कर 29वें स्थान पर) और जिम्बाब्वे के सीन विलियम्स (तीन स्थान ऊपर चढ़कर 47वें स्थान पर) श्रृंखला के बाद बल्लेबाजी रैंकिंग में ऊपर आने वाले अन्य खिलाड़ी हैं। स्कॉटलैंड के बल्लेबाज जॉर्ज मुन्से आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप लीग 2 में कनाडा के खिलाफ मैच विजयी 84 रनों की नाबाद पारी के बाद तीन स्थान ऊपर चढ़कर 34वें

स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका के टोनी डी जोंजी 67वें से 64वें स्थान पर आ गए हैं। एकदिवसीय गेंदबाजी रैंकिंग में दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर केशव महाराज ने श्रीलंका के स्पिनर महेश तीक्षाना को पछाड़कर शीर्ष स्थान हासिल किया है। उन्होंने लीड्स में इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में 22 रन देकर चार विकेट लिए थे। जोफ्रा आर्चर (छह स्थान ऊपर 19वें स्थान पर) और लुंगी एनगिडी (पांच स्थान ऊपर 23वें स्थान पर) भी मैच के बाद गेंदबाजी रैंकिंग में ऊपर आए हैं। असिथा फर्नांडो छह स्थान ऊपर 31वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि दिलशान मदुशंका ने हारे में पहले वनडे में 62 रन देकर चार विकेट लिए थे, जिसमें एक हैट्रिक भी शामिल थी, जिससे वह 60वें से 52वें स्थान पर पहुँच गए हैं। आईसीसी पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी रैंकिंग में अफगानिस्तान के बल्लेबाज इब्राहिम जादरान और सेदिकुल्लाह अटल ने शारजाह में त्रिकोणीय श्रृंखला के मैच में क्रमशः 65 और 64 रन बनाकर पाकिस्तान को हराने में मदद करने के बाद बड़ी प्रगति की है। जादरान 12 पायदान ऊपर चढ़कर 20वें स्थान पर पहुंच गए हैं, अटल 346 पायदान ऊपर चढ़कर 127वें स्थान पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तानी बल्लेबाज हसन नवाज (दो पायदान ऊपर चढ़कर संयुक्त 31वें स्थान पर) बल्लेबाजी रैंकिंग में बढ़त हासिल करने वालों में शामिल हैं, जबकि सूफियान मुकीम (11 पायदान ऊपर चढ़कर 22वें स्थान पर), शाहीन अफरीदी (आठ पायदान ऊपर चढ़कर 26वें स्थान पर) और मोहम्मद नवाज (15 पायदान ऊपर चढ़कर 43वें स्थान पर) गेंदबाजी रैंकिंग में छलांग लगाने वाले खिलाड़ियों में शामिल हैं। नबी अंतरराष्ट्रीय टी-20 ऑलराउंडरों की सूची में वह एक पायदान ऊपर चढ़कर दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं।

जर्मनी के साथ व्यापार सुगमता, बाजार पहुंच को मजबूत करने पर की बातचीत: गोयल

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सर्राफा यहां जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वाडेफुल के साथ विश्व व्यापार में बदलते परिदृश्य के बीच दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर बातचीत की। गोयल ने एक्स पोस्ट में बताया कि भारत और जर्मनी के व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों के साथ एक बैठक की सह-अध्यक्षता की। इस दौरान व्यापार सुगमता, नियामक ढांचे और बाजार पहुंच को मजबूत करने पर चर्चा की। गोयल ने बताया कि जर्मनी के विदेश मंत्री वाडेफुल के साथ भारत और जर्मनी के व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों के साथ बैठक में हमने व्यापार सुगमता, नियामक ढांचे और बाजार पहुंच को मजबूत करने पर चर्चा की। वाडेफुल के साथ एक उपयोगी बैठक हुई। गोयल ने कहा, हमने रक्षा, अंतरिक्ष, नवाचार और ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में सहयोग के अवसरों पर भी चर्चा की, जिससे हमारी साझेदारी की अपार संभावनाओं पर जोर दिया गया। उन्होंने बताया कि हमारी चर्चा द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ावा देने पर केंद्रित रही, साथ ही साझा विकास और समृद्धि के लिए नवाचार, स्थिरता, प्रौद्योगिकी और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशने पर भी केंद्रित रही। जर्मनी के विदेश मंत्री वाडेफुल दो दिवसीय दौरे पर दो सितंबर को भारत पहुंचे थे।

विक्रान इंजीनियरिंग का शेयर निर्गम मूल्य से करीब 3 फीसदी की बढ़त के साथ सूचीबद्ध

मुंबई। विक्रान इंजीनियरिंग लिमिटेड का शेयर अपने निर्गम मूल्य 97 रुपये से लगभग तीन फीसदी की बढ़त के साथ शेयर बाजार में सूचीबद्ध हुआ। कंपनी का बाजार मूल्यांकन 2,561.06 करोड़ रुपये रहा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) पर विक्रान इंजीनियरिंग की शेयर की शुरुआत 99.70 रुपये पर हुई, जो निर्गम मूल्य से 2.78 फीसदी की बढ़त है। इसके बाद में यह 4.52 फीसदी चढ़कर 101.39 रुपये पर पहुंच गया। नेशनल स?टॉक एक?सचेंज पर यह दो फीसदी की बढ़त के साथ 99 रुपये पर सूचीबद्ध हुआ। विक्रान इंजीनियरिंग के 772 करोड़ रुपये के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) को इस इश?यू को प्रस्तावित 92-97 रुपये प्राइस बैंड पर बोली के अंतिम दिन गत शुक्रवार तक 23.59 गुना अभिदान मिला था। ये आईपीओ 721 करोड़ रुपये के नए शेयर और प्रवर्तकों द्वारा 51 करोड़ रुपये की बिक्री पेशकश (ओएफएस) का संयोजन था। विक्रान इंजीनियरिंग लिमिटेड के आईपीओ में नया इश्यू और बिक्री प्रस्ताव दोनों शामिल हैं। मुंबई स्थित यह कंपनी नए शेयर की बिक्री से प्राप्त 541 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के वित्तपोषण और शेष राशि का इस्तेमाल कंपनी के सामान्य कामकाज के लिए करेगी। विक्रान इंजीनियरिंग लिमिटेड तेजी से बढ़ती भारतीय इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण कंपनियों में से एक है।

मॉयल का अगस्त में 17 फीसदी सालाना वृद्धि के साथ रिकॉर्ड 1.45 लाख टन उत्पादन

नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड (मॉयल) ने अगस्त में अब तक का सर्वाधिक 1.45 लाख टन उत्पादन किया है, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 17 फीसदी की वृद्धि है। कंपनी ने अगस्त में 1.13 लाख टन की बिक्री की है, जो सालाना आधार पर 25.6 फीसदी की उल्लेखनीय वृद्धि है। इस्पात मंत्रालय ने जारी एक बयान में बताया कि कंपनी ने अप्रैल-अगस्त 2025 के दौरान मॉयल ने 7.92 लाख टन उत्पादन के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज किया, जो सालाना आधार पर 9.3 फीसदी की वृद्धि है। इसके अलावा 50,621 मीटर अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग सालाना आधार पर 8.6 फीसदी वृद्धि के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। मॉयल के सीएमडी अजीत कुमार सक्सेना ने अगस्त महीने के इस रिकॉर्ड प्रदर्शन के लिए टीम को बधाई दी और चुनौतीपूर्ण मौसम की स्थिति में भी उत्पादन और बिक्री में वृद्धि हासिल करने के लिए उनके अथक प्रयासों की सराहना की है। उत्पादन आंकड़ों की घोषणा के बाद मॉयल के शेयरों में 8.4 फीसदी की वृद्धि हुई और बीएसई पर यह 374.1 रुपये प्रति शेयर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। कंपनी का बाजार पूंजीकरण 7,359.04 करोड़ रुपये रहा।

ब्रिस्कपे-फियो करारः निर्यातकों को विदेश से भुगतान प्राप्त करने में होगी आसानी

नई दिल्ली। सीमा-पार भुगतान सुविधा मंच, ब्रिस्कपे ने भारतीय निर्यातकों के शीर्ष निकाय फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (फियो) के साथ यहां एक समझौता-पत्र पर हस्ताक्षर किये जिसके तहत वह फियो के सदस्यों की मदद करेगी। कंपनी ने एक विज्ञप्ति में कहा कि इस साझेदारी का उद्देश्य निर्यातकों, विशेष रूप से छोटे निर्यातकों सरल और किफायती तरीके से डिज़िटल भुगतान समाधान उपलब्ध कराना है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि भारत के निर्यात क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों (एमएसएमई) की भूमिका तेजी से बढ़ी है। यहां निर्यात भवन में इस समझौते पर हस्ताक्षर के दौरान फियो के महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डॉ. अजय सहाय, ब्रिस्कपे के सह-संस्थापक एवं मुख्य परिचालन अधिकारी इंदुनाथ चौधरी और फ़ियो तथा ब्रिस्कपे के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे हस्ताक्षर किया गया। श्री चौधरी ने कहा, ब्रिस्कपे का लक्ष्य प्राथमिक क्षेत्रों में भी निर्यातकों तक नवीनतम सीमा-पार भुगतान समाधान उपलब्ध कराना है। फियो के डॉ. सहाय ने कहा , समयबद्ध और सुचारू रूप से भुगतान सुनिश्चित करना निर्यात तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ब्रिस्कपे के साथ हमारा सहयोग उन डिज़िटल समाधानों को रेखांकित करने हेतु एक मंच प्रदान करता है।

जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर अब नहीं लगेगा जीएसटी : सीतारमण

एजेंसी

नई दिल्ली। जीएसटी परिषद ने पॉलिसी धारकों को बड़ी राहत दी है। अब व्यक्तिगत जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के प्रीमियम सस्ते हो जाएंगे। दरअसल, इन बीमा उत्पादों को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से छूट दे दी गई है। संशोधित दरें 22 सितंबर, नवरात्रि के पहले दिन से लागू होंगी।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक के बाद आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में ऐलान किया कि सभी तरह की व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसी और उनके पुनर्बीमा पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इनमें टर्म लाइफ, यूलिप या एंडोमेंट पॉलिसी शामिल हैं। फिलहाल इन पर अभी 18 फीसदी जीएसटी लगता है। उन्होंने बताया कि जीएसटी परिषद के फैसले के बाद अब इनपर पूरी तरह से छूट दी जाएगी। इस बदलाव के

साथ सभी व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसियां- जिनमें टर्म लाइफ, यूलिप और एंडोमेंट प्लान शामिल हैं और साथ ही उनका पुनर्बीमा भी अब शून्य जीएसटी श्रेणी में आ जाएगा। यह छूट सभी व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों, जिनमें फैमिली फ्लोटर और वरिष्ठ नागरिक योजनाएँ शामिल हैं और उनके पुनर्बीमा पर भी लागू होगी। सीतारमण ने कहा कि बीमा पर जीएसटी समाप्त करने से आम आदमी के लिए यह अधिक किफायती हो जाएगा। इससे देशभर में बीमा कवरेज के विस्तार में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि बीमा के अलावा जीएसटी परिषद ने कई आवश्यक वस्तुओं पर भी कर दरों में कटौती की है। सीतारमण ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में 33 जीवन रक्षक दवाओं पर 12 फीसदी से जीएसटी की दर को शून्य कर दिया गया है, जबकि कैंसर, दुर्लभ और दीर्घकालिक बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली तीन महत्वपूर्ण दवाओं को भी कर मुक्त कर दिया गया है। इसके अलावा यूएचटी दूध, पनीर और रोटी, चपाती और पराठे जैसी सभी भारतीय रोटियों पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। नई दरें 22 सितंबर से पूरे देश में लागू होंगी।

जीएसटी दरों में व्यापक सुधारों को मंजूरी, दैनिक इस्तेमाल के सामान पर दरें घटीं

एजेंसी

नई दिल्ली। जीएसटी परिषद ने आम सहमति से माल एवं सेवा कर जीएसटी में व्यापक सुधारों को मंजूरी दे दी है। इन सुधारों के तहत साबुन, साइकिल, टीवी और व्यक्तिगत स्वास्थ्य तथा जीवन बीमा पॉलिसी जैसे आम उपयोग के उत्पादों पर जीएसटी की दरें कम की गई हैं। छेना, पनीर, रोटी और पराठा पर कोई जीएसटी नहीं देना होगा। इसके अलावा जीवन रक्षक दवाओं पर भी जीएसटी शून्य होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में लिए गए निर्णय के बारे में यहां आयोजित एक प्रेस कांफ्रेंस में जानकारी देते हुए कहा कि जीएसटी में पांच फीसदी और 18 फीसदी की दो-स्तरीय कर संरचना को मंजूरी दी गई है। उन्?होंने बताया कि गुटखा, तंबाकू और तंबाकू उत्पादों तथा सिगरेट को छोड़कर सभी उत्पादों पर नई दरें 22 सितंबर यानी नवरात्रि के पहले दिन से लागू होंगी। सीतारमण ने बताया कि जीएसटी में व्यापक सुधारों के तहत बाल में लगाने वाले तेल, साबुन, साइकिल आम और मध्यम वर्ग की वस्तुओं पर जीएसटी की दर 12 फीसदी या 18 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि जीएसटी परिषद ने लोगों को राहत देते हुए रोजमर्रा के उपयोग वाले सामानों पर जीएसटी दरों में कटौती की है। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के प्रीमियम पर जीएसटी से छूट मिलेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि इसके अलावा छोटी कारों और 350 सीसी तक के दोपहिया वाहनों पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। तिपहिया वाहन पर भी अब 18 फीसदी कर लगेगा। उन्होंने कहा कि तंबाकू, पान मसाला और सिगरेट पर जीएसटी 40 फीसदी की विशेष दर से लगेगा। सीतारमण ने कहा, ''यह केवल जीएसटी में सुधार नहीं है, बल्कि संरचनात्मक सुधारों और लोगों की जीवन को सुगम बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है।''

स्टॉक मार्केट में ओवल प्रोजेक्ट्स की सपाट एंट्री, मामूली फायदे में आईपीओ निवेशक

एजेंसी

नई दिल्ली। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, अर्बन डेवलपमेंट और एनर्जी सेक्टर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करने वाली कंपनी ओवल प्रोजेक्ट्स इंजीनियरिंग के शेयरों ने आज स्टॉक मार्केट में फ्लैट एंट्री करके अपने आईपीओ निवेशकों को निराश कर दिया। आईपीओ के तहत कंपनी के शेयर 85 रुपये के भाव पर जारी किए गए थे। आज बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर इसकी लिस्टिंग सिर्फ 0.29 प्रतिशत प्रीमियम के साथ 85.25 रुपये के स्तर पर हुई। हालांकि लिस्टिंग के बाद हुई मामूली लिवाली के कारण कंपनी के शेयरों के भाव में मामूली तेजी का रुख भी बना। सुबह 11 बजे तक कारोबार होने के बाद ओवल प्रोजेक्ट्स इंजीनियरिंग के शेयर 86 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहे थे। ओवल प्रोजेक्ट्स इंजीनियरिंग का 46.47 करोड़ रुपये का आईपीओ 28 अगस्त से 1 सितंबर के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इस आईपीओ को निवेशकों की ओर से भी फीका रिस्पॉन्स मिला था, जिसके कारण ये ओवरऑल 1.61 गुना सब्सक्राइब हो सका था। इनमें सिर्फ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए रिजर्व पोर्शन ही पूरा भर सका था, जबकि दूसरे वर्गों में पूरा सब्सक्रिप्शन भी नहीं आ सका था। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए रिजर्व पोर्शन 6.21 गुना सब्सक्राइब हुआ था। वहीं, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (एनआईआई) के लिए रिजर्व पोर्शन में सिर्फ 0.82 गुना सब्सक्रिप्शन आया था। इसी तरह रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व पोर्शन 0.83 गुना सब्सक्राइब हो सका था। इस आईपीओ के तहत 10 रुपये फेस वैल्यू वाले 54,99,200 नए शेयर जारी किए गए हैं। आईपीओ के जरिये जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने और आम कॉरपोरेट उद्देश्यों में करेगी।

कंपनी की वित्तीय स्थिति की बात करें तो प्रॉस्पेक्टस में किए गए दावे के मुताबिक इसकी वित्तीय सेहत लगातार मजबूत हुई है। वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी को 3.19 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था, जो अगले वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़ कर 4.40 करोड़ रुपये और 2024-25 में उछल कर 9.33 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। इस दौरान कंपनी का राजस्व 27 प्रतिशत वार्षिक से अधिक की चक्रवृद्धि दर (कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट) से बढ़ कर 103.44 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। इस दौरान कंपनी पर कर्ज में भी लगातार बढ़ोतरी हुई। वित्त वर्ष 2022-23 के आखिर में कंपनी का कर्ज 32.21 करोड़ रुपये, जो वित्त वर्ष 2023-24 के आखिर में बढ़ कर 32.41 करोड़ रुपये हो गया। इसी तरह वित्त वर्ष 2024-25 के आखिर में कंपनी का कर्ज उछल कर 53.70 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया।

जीएसटी दरों में बढ़ोतरी से कोल्ड ड्रिंक हो जाएगा महंगा, नई दरें 22 सितंबर से होंगी लागू

एजेंसी

नई दिल्ली। जीएसटी परिषद ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था में व्यापक बदलाव को मंजूरी दे दी। इस बदलाव से कोका-कोला एवं पेप्सी जैसे लोकप्रिय शीतल पेय और अन्य गैर-अल्कोहल पेय पदार्थ अब महंगे हो जाएंगे। जीएसटी परिषद ने कार्बोनेटेड पेय पदार्थों पर जीएसटी की दर को 28 फीसदी से बढ़ाकर 40 फीसदी करने को अपनी मंजूरी दी है। नई दरें 22 सितंबर, यानी नवरात्रि के पहले दिन से लागू होंगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक के बाद यहां आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में इसकी जानकारी दी। सीतारमण ने मीडिया को दी जानकारी में बताया कि जीएसटी की नई व्यवस्था में व्यापक सुधारों के तहत अब जीएसटी परिषद ने फलों से बने पेय या फलों के रस वाले कार्बोनेटेड पेय पदार्थों पर भी जीएसटी की दर को 28 फीसदी से बढ़ाकर 40 फीसदी कर दिया है।

उन्होंने बताया कि जीएसटी की दरों में बढ़ोतरी करने से कोल्ड ड्रिंक अतिरिक्त चीनी या अन्य मीठा पदार्थ या स्वाद वाले सभी उत्पादों पर भी जीएसटी की दर 28 फीसदी से बढ़ाकर 40 फीसदी कर दी है।

अब महंगा हो जाएगा। इसके साथ ही अन्य गैर-अल्कोहल पेय पदार्थ भी महंगे हो जाएंगे, क्योंकि इन वस्तुओं पर जीएसटी की मौजूदा दर 18 फीसदी से बढ़ाकर 40 फीसदी कर दी गई है। जीएसटी परिषद ने हालांकि, फलों के गूदे या फलों के रस आधारित पेय (फलों के कार्बोनेटेड पेय या फलों के रस वाले कार्बोनेटेड पेय को छोड़कर) पर जीएसटी की दर 12 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी कर दी गई है।

भारत में टिकाऊ विमान ईंधन का निर्यातक बनने की क्षमता: राममोहन नायडू

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने सर्राफा कहा कि भारत में न केवल सतत विमानन ईंधन (एसएएफ) की अपनी मांग को पूरा करने की क्षमता है, बल्कि वह एक निर्यातक के रूप में भी उभर सकता है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जारी एक बयान में बताया कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ) के साथ साझेदारी में और यूरोपीय संघ के समर्थन से यहां भारत के लिए सतत विमानन ईंधन (एसएएफ) व्यवहार्यता अध्ययन को जारी करने के अवसर पर यह बात कही। नायडू ने कहा कि भारत के पास टिकाऊ विमानन ईंधन (एसएएफ) का निर्यातक बनने की क्षमता है, जो कार्बन उत्सर्जन कम करने का एक व्यावहारिक समाधान है। उन्होंने कहा कि देश में 75

करोड़ टन से अधिक बायोमास और करीब 23 करोड़ टन अतिरिक्त कृषि अवशेष उपलब्ध हैं। उन्होंने इस अध्ययन का जिक्र करते हुए कहा कि एसएएफ विमानन क्षेत्र को कार्बन-मुक्त करने के लिये एक व्यावहारिक और त्वरित समाधान है, जो पारंपरिक ईंधन की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 80 फीसदी तक कम कर सकता है। मंत्री ने कहा कि भारत वर्ष 2027 तक एटीएफ में एक फीसदी, 2028 तक दो फीसदी और 2030 तक पांच फीसदी एसएएफ के मिश्रण का लक्ष्य लेकर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मंत्रालय के मुताबिक इस समारोह को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू, नागरिक उड्डयन सचिव समीर कुमार सिन्हा, नागरिक उड्डयन महानिदेशक फैज अहमद और आईसीएओ के वायु परिवहन ब्यूरो में पर्यावरण उप निदेशक जेन हूपे ने संबोधित किया। उल्लेखनीय है कि बायोमास की श्रेणी में ऐसे प्राकृतिक संसाधन आते हैं जिनका इस्तेमाल ऊर्जा एवं ईंधन उत्पादन के लिए किया जा सकता है। इनमें कृषि अवशिष्ट, वानिकी उपज, पशु अपशिष्ट और अन्य जैविक पदार्थ शामिल हैं।

श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र का आईपीओ 10 सितंबर को खुलेगा, प्राइस बैंड 155-165 रुपये प्रति शेयर

एजेंसी

नई दिल्ली/मुंबई। आभूषण कंपनी श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र लिमिटेड का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) 10 सितंबर को खुलेगा। निवेशक इसमें निवेश करने के लिए 12 सितंबर तक बोली लगा सकते हैं। कंपनी ने इसके लिए मूल?य का दायरा (प्राइस बैंड) 155-165 रुपये प्रति शेयर तय किया है। इसके शेयर 17 सितंबर को बीएसई और एनएसई पर सूचीबद्ध होंगे।आभूषण कंपनी श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र ने सर्राफा जारी एक बयान में बताया कि उसका इश्यू 10 सितंबर को खुलकर 12 सितंबर को बंद होगा। कंपनी ने 10 अंकित मूल्य वाले आईपीओ के लिए मूल्य का दायरा 155-65 रुपये प्रति शेयर तय किया है। यह इश्यू 2.43 करोड़ नए शेयरों का निर्गम है, जिसमें कोई बिक्री पेशकश (ओएफएस) शामिल नहीं है। कंपनी के मुताबिक निवेशक इसमें न्यूनतम 90 इक्विटी शेयरों और उसके बाद 90 इक्विटी शेयरों के गुणकों में बोली लगा सकते हैं। श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र लिमिटेड नए शेयरों की बिक्री से प्राप्त करीब 280 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग कंपनी की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं और सामान्य कंपनी कामकाज के लिए करेगी। मुंबई स्थित वर्ष 2009 में स्थापित आभूषण कंपनी श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र लिमिटेड 18 कैरेट और 22 कैरेट सोने में तैयार विभिन्न रत्नों और अर्ध-कीमती पत्थरों से सजे मंगलसूत्रों की डिजाइन निर्माण और विपणन में लगा हुआ है। यह कंपनी भारत के 24 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में कॉर्पोरेट ग्राहकों, थोक ज्वैलर्स और खुदरा विक्रेताओं सहित ग्राहकों की एक विस्तृत श्रृंखला को सेवाएं प्रदान करती है।

सर्राफा बाजार में 1.07 लाख के पार पहुंचा सोना, चांदी की कीमत में मामूली गिरावट

एजेंसी

नई दिल्ली। घरेलू सर्राफा बाजार में सोने की कीमत में तेजी का दौर आज भी जारी है। सोने की कीमत में आज 700 रुपये से लेकर 770 रुपये प्रति 10 ग्राम तक की तेजी आई है। हालांकि चांदी के भाव में आज मामूली गिरावट आई है। कीमत में तेजी आने के कारण देश के ज्यादातर सर्राफा बाजारों में 24 कैरेट सोना आज प्रति 10 ग्राम 1,06,860 रुपये से लेकर 1,07,010 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। दूसरी ओर, 22 कैरेट सोना आज 97,950 रुपये से लेकर 98,100 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। चांदी के भाव में मामूली गिरावट आने के कारण ये चमकीली धातु दिल्ली सर्राफा बाजार में आज 1,27,000 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बिक रही है। दिल्ली में 24 कैरेट सोना आज 1,07,010 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 98,100 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई

है। वहीं, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,06,860 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 97,950 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 1,06,910 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 98,000 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। इन प्रमुख शहरों के अलावा चेन्नई में 24 कैरेट सोना आज 1,06,860 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर और 22 कैरेट सोना 97,950 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है। कोलकाता में भी 24 कैरेट सोना 1,06,860 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 97,950 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। लखनऊ के सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना आज 1,07,010 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर और 22 कैरेट सोना 98,100 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। पटना में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,06,910 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 98,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। जयपुर में 24 कैरेट सोना 1,07,010 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 98,100 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

जीएसटी दर में बदलाव से छोटी कार, 350 सीसी तक की बाइक होंगी सस्ती

एजेंसी

नई दिल्ली। जीएसटी परिषद ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था में व्यापक बदलाव को अपनी मंजूरी दे दी। इसके तहत जीएसटी में पांच और 18 प्रतिशत की दो-स्तरीय कर संरचना को मंजूरी दी गई है। जीएसटी दरों में व्यापक बदलाव से छोटी कारें और मोटरसाइकिल सस्ती होंगी। नई दरें 22 सितंबर, यानी नवरात्रि के पहले दिन से लागू होंगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक के बाद यहां आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में इसकी जानकारी दी। वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग के सचिव अरविंद श्रीवास्तव ने बताया कि जीएसटी की दरों में संशोधन के तहत 1,200 सीसी से कम और 4,000 मिमी से कम लंबाई वाले पेट्रोल, एलपीजी और सीएनजी की दर से जीएसटी लगेगा, जबकि वर्तमान में यह 28 फीसदी है। उन्होंने बताया कि 1,200 सीसी से अधिक

वाहन तथा 1,500 सीसी और 4,000 मिमी तक लंबाई वाले डीजल वाहनों पर मौजूदा 28 फीसदी की जगह 18 फीसदी कर लगेगा। वहीं, 350 सीसी तक की मोटरसाइकिल पर 18 फीसदी और 4,000 मिमी से अधिक लंबी सभी वाहनों के साथ-साथ 350 सीसी से अधिक की मोटरसाइकिल और रेसिंग कार पर 40 फीसदी की दर से जीएसटी शुल्क लगाया जाएगा।

डॉलर की तुलना में मजबूत हुआ रुपया, 10 पैसे की तेजी के साथ बंद हुई भारतीय मुद्रा

नई दिल्ली। कच्चे तेल की कीमत में गिरावट आने, डॉलर इंडेक्स के कमजोर पड़ने और स्टॉक मार्केट में विदेशी निवेशकों की लिवाली का असर भारत के मुद्रा बाजार में साफ नजर आया। मुद्रा बाजार में बने सकारात्मक माहौल और मुद्रा बाजार में डॉलर की आवक बढ़ने के कारण रुपया आज डॉलर की तुलना में मजबूत होकर बंद हुआ। भारतीय मुद्रा आज डॉलर की तुलना में 10 पैसे उछल कर 88.07 (अनंतिम) के स्तर पर बंद हुई। इसके पहले पिछले कारोबारी दिन सोमवार को भारतीय मुद्रा 88.17 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुई थी। रुपये ने आज के कारोबार की शुरुआत भी मामूली मजबूती के साथ ही की थी। इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में भारतीय मुद्रा ने आज सुबह डॉलर के मुकाबले 2 पैसे की बढ़त के साथ 88.15 रुपये के स्तर से कारोबार की शुरुआत की थी। आज का कारोबार शुरू होने के बाद कुछ देर के लिए रुपया फिसल कर 88.19 रुपये के स्तर तक भी आया, लेकिन इसके बाद स्टॉक मार्केट में विदेशी निवेशकों की लिवाली शुरू हो जाने और अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत में गिरावट आने के कारण रुपये की चाल में तेजी आ गई। बाजार में बने सकारात्मक माहौल के कारण रुपया 19 पैसे की तेजी के साथ 87.98 के स्तर तक पहुंच गया। हालांकि, दूसरे सत्र में एक बार फिर डॉलर की मांग में थोड़ी तेजी आने के कारण रुपये की चाल में दोबारा गिरावट आ गई।

दो दिन के बाद शेयर बाजार में लौटी तेजी, शुरुआती कमजोरी के बाद उछले सेंसेक्स और निफ्टी

एजेंसी

नई दिल्ली। घरेलू शेयर बाजार सर्राफा दिन के दूसरे सत्र में हुई खरीदारी के सपोर्ट से मजबूती के साथ बंद होने में सफल रहा। आज के कारोबार की शुरुआत भी तेजी के साथ हुई थी। हालांकि, दिन के पहले सत्र में लिवालों और बिकवालों के बीच लगातार खींचतान चलती रही। इसके बाद दिन के दूसरे सत्र में बाजार में जोरदार खरीदारी देखने को मिली, जिसकी वजह से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों सूचकांकों ने भी बढ़त हासिल कर ली। पूरे दिन के कारोबार के बाद सेंसेक्स 0.51 प्रतिशत और निफ्टी 0.55 प्रतिशत की मजबूती के साथ बंद हुए। आज दिन भर के कारोबार के दौरान मेटल, फार्मास्यूटिकल, पीएसयू बैंक और ऑटोमोबाइल सेक्टर के शेयरों में लगातार खरीदारी होती रही। इसी तरह एफएमसीजी, रियल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑयल एंड गैस और एनर्जी इंडेक्स में भी तेजी का रुख बना रहा। दूसरी ओर आईटी, टेक और मीडिया सेक्टर के शेयरों में बिकवाली का दबाव बना रहा। ब्रॉडर मार्केट में भी आज खरीदारी का जोर बना रहा, जिसके कारण बीएसई का मिडकैप इंडेक्स 0.63 प्रतिशत की मजबूती के साथ बंद हुआ। इसी तरह स्मॉलकैप इंडेक्स ने 0.90 प्रतिशत की तेजी के साथ आज के कारोबार का अंत किया। आज शेयर बाजार में आई मजबूती के कारण स्टॉक मार्केट के निवेशकों की संपत्ति में करीब तीन लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हो गई। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन आज के कारोबार के बाद बढ़ कर 452.87 लाख करोड़ रुपये (अनंतिम) हो गया। जबकि पिछले कारोबारी दिन यानी मंगलवार को इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 449.90 लाख करोड़ रुपये था। इस तरह निवेशकों को आज के कारोबार से करीब 2.97 लाख करोड़ रुपये का मुनाफा हो गया। आज दिन भर के कारोबार में बीएसई में 4,270 शेयरों में एक्टिव ट्रेडिंग हुई। इनमें 2,640 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि 1,463 शेयरों में गिरावट का रुख रहा, वहीं 167 शेयर बिना किसी उतार चढ़ाव के बंद हुए। एनएसई में आज 2,778 शेयरों में एक्टिव ट्रेडिंग हुई। इनमें से 1,884 शेयर मुनाफा कमा कर हरे निशान में और 894 शेयर नुकसान उठा कर लाल निशान में बंद हुए। इसी तरह सेंसेक्स में शामिल 30 शेयरों में से 22 शेयर बढ़त के साथ और 8 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। जबकि निफ्टी में शामिल 50 शेयरों में से 35 शेयर हरे निशान में और 15 शेयर लाल निशान में बंद हुए। बीएसई का सेंसेक्स आज 138.11 अंक की मजबूती के साथ 80,295.99 अंक के स्तर पर खुला। कारोबार की शुरुआत होते ही लिवालों और बिकवालों के बीच खींचतान शुरू हो गई, जिसकी वजह से इस सूचकांक की चाल भी ऊपर नीचे होने लगी। बिकवाली के दबाव में सेंसेक्स 153.28 अंक की कमजोरी के साथ 80,004.60 अंक तक गिर गया। हालांकि, दिन के दूसरे सत्र में खरीदारों ने पूरी तरह से बाजार पर अपना कब्जा जमा लिया। लगातार हो रही लिवाली के सपोर्ट से आज का कारोबार खत्म होने के कुछ देर पहले ये सूचकांक 513.40 अंक की मजबूती के साथ 80,671.28 अंक तक पहुंचने में सफल रहा। अंत में इंट्रा-डे सेटलमेंट के कारण हुई मामूली बिकवाली की वजह से सेंसेक्स ऊपरी स्तर से करीब 100 अंक फिसल कर 409.83 अंक की बढ़त के साथ 80,567.71 अंक के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स की तरह ही एनएसई के निफ्टी ने आज 36.90 अंक उछल कर 24,616.50 अंक के स्तर से कारोबार की शुरुआत की। बाजार खुलने के बाद पहले सत्र के दौरान इस सूचकांक की चाल में लगातार उतार चढ़ाव होता रहा। बिकवाली के दबाव में निफ्टी 46.40 अंक टूट कर 24,533.20 अंक तक गिर गया।

ट्रंप का भारत पर हमलाः 'भारत ने अमेरिका को नुकसान पहुंचाया'

एजेंसी

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर एक बार फिर से हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भारत ने वर्षों तक अमेरिका को व्यापार के मोर्चे पर 'नुकसान' पहुंचाया है, लेकिन अब वह शून्य-शुल्क व्यापार की पेशकश कर रहा है। ट्रंप का यह बयान दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों पर एक नई बहस को जन्म दे सकता है। ट्रंप ने भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को हमेशा से ही असंतुलित बताया है।

शून्य-शुल्क की पेशकशः ट्रंप ने कहा कि भारत की यह पेशकश सिर्फ दिखावा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत ने पहले अमेरिका से अनुचित लाभ उठाया, और अब जब वह मजबूत स्थिति में हैं, तो वह इस तरह की पेशकश कर रहा है। ट्रंप का यह बयान भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर चल रही बातचीत के बीच आया है। यह देखना होगा कि इस बयान का दोनों देशों के बीच चल रही बातचीत पर क्या असर पड़ता है।

संबंधों पर असरः ट्रंप के इस बयान से दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों में तनाव बढ़ सकता है। भारत सरकार ने इस पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि, यह तय है कि यह बयान भारत और अमेरिका के बीच चल रही व्यापारिक बातचीत में एक बड़ी बाधा बन सकता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने रूसी समकक्ष को दी परोक्ष धमकी

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के संबंध में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दिए गए अपने संदेश के बारे में पूछे जाने पर चेतावनी जारी की। सीएनएन की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि ट्रंप ने ओवल ऑफिस से कहा, 'राष्ट्रपति पुतिन के लिए मेरा कोई संदेश नहीं है। वह जानते हैं कि मैं किस स्थिति में हूँ, और वह किसी न किसी तरह से कोई न कोई फैसला लेंगे। उनका जो भी फैसला होगा, हम या तो उससे खुश होंगे या नाखुश, और अगर हम उससे नाखुश हैं, तो आप देखेंगे कि क्या होगा, राष्ट्रपति ने परोक्ष धमकी देते हुए कहा। रूस के खिलाफ प्रशासन की अब तक की कार्रवाइयों - या उनकी कमी - के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप स्पष्ट रूप से उत्तेजित हो गए। ट्रंप ने कहा, ÷आपको कैसे पता कि कोई कार्रवाई नहीं हुई है? क्या आप कहेंगे कि चीन के अलावा सबसे बड़े खरीदार भारत पर द्वितीयक प्रतिबंध लगाना लगभग बराबर है। क्या आप कहेंगे कि कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई जिससे रूस को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ हो?' उन्होंने कहा, 'आप इसे कोई कार्रवाई नहीं कहते।'

इज़रायल ने हमास के युद्धविराम प्रस्ताव को ठुकराया, गाजा सिटी पर हमले जारी रखने का लिया संकल्प

गाजा/यरूशलम। इज़रायल ने गाजा में युद्ध समाप्त करने के लिए एक व्यापक युद्धविराम समझौते पर पहुँचने के हमास के प्रस्ताव को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि उसकी सेना गाजा सिटी पर एक बड़े हमले की तैयारी जारी रखेगी। हमास ने जारी एक प्रेस बयान में एक 'व्यापक समझौते' पर पहुँचने की अपनी इच्छा दोहराई जिसके तहत गाजा में इज़रायली बंधकों को इज़रायल में बंद फ़िलिस्तीनी कैदियों की एक निश्चित संख्या के बदले रिहा किया जाएगा। हमास के अनुसार, इस समझौते में स्थायी युद्धविराम, गाजा से इज़रायली सेना की वापसी, मानवीय सहायता और आवश्यक आपूर्ति के लिए सीमा चौकियों को फिर से खोलना और पुनर्निर्माण प्रयासों की शुरुआत भी शामिल होगी। हमास ने गाजा के नागरिक मामलों के प्रबंधन की तत्काल ज़िम्मेदारी लेने के लिए टेक्नोक्रेटों से युक्त एक स्वतंत्र राष्ट्रीय प्रशासन की स्थापना का भी समर्थन किया। इसके जवाब में इज़रायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बयान को 'एक भ्रामक' बताकर खारिज कर दिया। उनके कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में नेतन्याहू ने कहा कि इज़रायल युद्ध समाप्त करने के लिए तभी सहमत होगा जब हमास गाजा पट्टी पर पूर्ण इज़रायली सुरक्षा नियंत्रण, हमास और गाजा का विसैन्यीकरण, एक गैर-फ़िलिस्तीनी प्रशासन की स्थापना और सभी बंधकों की रिहाई को स्वीकार कर ले।

ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर भारतीयों समेत कुछ खास समूहों के प्रवासियों को लाने के दावे से पीछे हटी

सिडनी। ऑस्ट्रेलिया की लिबरल सीनेटर जसिंटा नम्पिजिनपा प्राइस अपने उस दावे से पीछे हट गयी जिसमें कहा गया था कि देश की संघीय सरकार अपने वोटों को मजबूत करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों सहित कुछ खास समूहों के प्रवासियों को ला रही है। सिडनी मार्निंग हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक सुश्री प्राइस ने एबीसी के आफ्टरनून ब्रीफिंग कार्यक्रम में आव्रजन मुद्दों पर चर्चा के दौरान यह दावा किया था। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि ज्यादातर ऑस्ट्रेलियाई आव्रजन को लेकर चिंतित हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें लगता है कि लोग 'मुख्य संख्या या आने वाले प्रवासियों के स्वरुप' को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने कहा ,यह निश्चित रूप से मुख्य संख्या है और निश्चित रूप से इस सरकार का ध्यान अन्य देशों की बजाय विशिष्ट देशों से प्रवासियों को लाने पर है।

लिस्बन में इलेक्ट्रिक स्ट्रीटकार दुर्घटनाग्रस्त, 15 लोगों की मौत, 18 घायल

एजेंसी

लिस्बन । लिस्बन के सबसे प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षणों में से एक ग्लोरिया फनिक्युलर के दुर्घटनाग्रस्त होने से 15 लोगों की मौत हो गई और 18 अन्य घायल हो गए। घायलों में पांच की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह जानकारी स्थानीय मीडिया ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल इमरजेंसी के हवाले से दी। समाचार एजेंसी के अनुसार, पुर्तगाली राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा ने बेलेम पैलेस में गुरुवार से रविवार तक होने वाले पुस्तक महोत्सव को रद्द कर दिया है। राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित एक बयान के अनुसार, यह निर्णय लिस्बन में ग्लोरिया फनिक्युलर (इलेक्ट्रिक स्ट्रीटकार) से जुड़ी गंभीर दुर्घटना के पीड़ितों की स्मृति और शोक संतप्त परिवारों के प्रति एकजुटता में लिया गया है। सभी

दलों के नेताओं ने शोक व्यक्त किया और सरकार ने गुरुवार को राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया। लिस्बन के मेयर कार्लोस मोएदास ने इसे 'एक कठिन दिन' बताते हुए कहा कि शहर 'कड़ी मेहनत' कर रहा है। यूरोपीय संघ आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पुर्तगाली भाषा में पोस्ट करके अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने लिखा, 'मुझे प्रसिद्ध एलेवेडोर दा ग्लोरिया के पटरी से उतरने की खबर सुनकर दुख हुआ। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने कहा, 'वह लिस्बन में ग्लोरिया फनिक्युलर की भयानक दुर्घटना से स्तब्ध हैं।' पोस्ट में सांचेज ने पीड़ितों के परिवारों और पुर्तगाली लोगों के प्रति 'इस कठिन घड़ी में' 'अपना पूरा स्नेह और एकजुटता' व्यक्त की। उन्होंने आगे कहा, 'घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं।' इतालवी विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी ने लिखा कि उन्होंने पुर्तगाली विदेश मंत्री पाउलो रंगेल से मुलाकात की और 'पीड़ितों के प्रति अपनी एकजुटता' व्यक्त की। लिस्बन स्थित अमेरिकी दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में दुर्घटना के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। दूतावास ने लिखा, 'लिस्बन के ग्लोरिया फनिक्युलर के पटरी से उतरने की दुखद घटना से हम स्तब्ध हैं।

नेपाल में फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, वाट्सएप्प सहित अधिकांश सोशल मीडिया साइट पर प्रतिबंध का फैसला

एजेंसी

काठमांडू। सरकार ने संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में पंजीकरण न कराने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ्ग की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई बैठक में उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया जो निर्धारित समय सीमा के भीतर पंजीकरण नहीं कराया है। मंत्री गुरूंग ने बताया सरकार ने पिछली बार सभी सोशल मीडिया साइट्स को लिस्टिंग के लिए सात दिनों की समय सीमा दी थी। यह समय सीमा बीती रात 12 बजे समाप्त हो गई इसलिए आज यह निर्णय लिया गया। सरकार के इस फैसले के बाद नेपाल में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, वाट्सएप्प, यूट्यूब, गूगल, मैसेंजर आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निष्क्रिय करने के लिए नेपाल टेलीकॉम को पत्र भेज दिया गया है। नेपाल में अब तक सिर्फ टिकटक, वाइबर, निम्बज, विटक और पोपो लाइव ने ही कंपनी रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करवाया है।

पूर्वाचल प्लॉट घोटाले में ढाका की अदालत ने हसीना के बचाव की याचिका पर सुनवाई से इनकार किया

एजेंसी

ढाका। बांग्लादेश में ढाका की एक विशेष न्यायालय ने पूर्वांचल प्लॉट घोटाले में अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना का बचाव करने की अनुमति मांगने वाली याचिका पर आज सुनवाई करने से इनकार कर दिया। द डेली स्टार अखबार ने यह खबर याचिकाकर्ता वकील मोर्शेद हुसैन शाहीन के हवाले से अपनी वेबसाइट पर दी है। वकील शाहीन ने बताया कि न्यायाधीश मोहम्मद रबीउल आलम ने इस बाबत कुछ दिशा-निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि अदालत ने कहा है कि कानूनी बाधाओं के कारण इस मामले में राज्य की ओर से बचाव पक्ष नियुक्त करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

दरअसल, पूर्वाचल न्यू टाउन परियोजना के तहत भूखंडों के आवंटन में कथित अनियमितता को लेकर हसीना, रेहाना और ट्यूलिप सहित 23 लोगों के खिलाफ दर्ज भ्रष्टाचार के तीन मामलों में आज अदालत को अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज करने थे। भ्रष्टाचार निरोधक आयोग ने 12 से

14 जनवरी के बीच अपने ढाका एकीकृत जिला कार्यालय में इस बाबत छह अलग-अलग मामले दर्ज किए थे। भ्रष्टाचार निरोधक आयोग के अनुसार हसीना ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके पूर्वाचल न्यू टाउन परियोजना के सेक्टर 27 के राजनयिक क्षेत्र में अपने और अपने बेटे सजीब वाजेद जॉय और बेटी साइमा वाजेद पुतुल, रेहाना और उनके बेटे रदवान मुजीब सिद्दीक बॉबी और बेटी अजमीना के लिए अवैध रूप से छह भूखंड (प्रत्येक 10 कट्ठा) हासिल किए। मौजूदा नियमों के तहत वे इसके लिए अयोग्य थे।

हार्वर्ड विवि को ट्रंप प्रशासन के साथ टकराव में महत्वपूर्ण कानूनी जीत मिली

एजेंसी

वाशिंगटन (अमेरिका)। हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने ट्रंप प्रशासन के साथ टकराव में महत्वपूर्ण कानूनी जीत हासिल की। बोस्टन स्थित अमेरिकी जिला न्यायालय की न्यायाधीश एलिसन डी. बरोज ने कहा कि सरकार ने यहूदी-विरोधी भावना को जड़ से खत्म करने के नाम पर अरबों डॉलर के अनुसंधान कोष को रोककर कानून तोड़ा है। कानूनविद् कहते हैं कि यह फैसला हार्वर्ड को व्हाइट हाउस के साथ समझौता वार्ता में नई ताकत दे सकता है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर में बोस्टन स्थित अमेरिकी जिला न्यायालय की न्यायाधीश एलिसन डी. बरोज के फैसले की जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया है कि यह एकमात्र विश्वविद्यालय है जिसने अपने शोध निधि पर प्रशासन के लक्षित हमले के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। न्यायाधीश बरोज ने 84 पृष्ठों के अपने फैसले में लिखा, हमें यहूदी-विरोध के खिलाफ लड़ना होगा, लेकिन हमें अपने अधिकारों की भी रक्षा करनी होगी, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है और किसी भी लक्ष्य को दूसरे की वेदी पर बलिदान नहीं किया जाना चाहिए। चाहिए। उन्होंने कहा, हार्वर्ड वर्तमान में, भले ही देर से ही सही, यहूदी-विरोध से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है और जरूरत पड़ने पर और भी अधिक करने को तैयार है। न्यायाधीश एलिसन डी. बरोज ने कहा, अब अदालतों का काम है कि वे भी इसी तरह आगे आएं। संविधान द्वारा अपेक्षित शैक्षणिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कदम उठाएं। यह सुनिश्चित करें कि महत्वपूर्ण शोध को अनुचित रूप से मनमाने और प्रक्रियात्मक रूप से कमजोर अनुदानों से न रोका जाए, भले ही ऐसा करने से अपने एजेंडे के प्रति प्रतिबद्ध सरकार के क्रोध का जोखिम हो, चाहे इसके लिए उसे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। निर्णय के एक भाग के रूप में, न्यायाधीश बरोज ने कहा कि ट्रंप प्रशासन हार्वर्ड के संघीय अनुसंधान निधि पर %%अपने प्रथम संशोधन अधिकारों के प्रयोग के प्रतिशोध में या नागरिक अधिकार कानून की शर्तों के अनुपालन के बिना भेदभाव के किसी भी कथित आधार पर नई रुकावटें जारी नहीं कर सकता। व्हाइट हाउस ने इस फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता लिज ह्यूस्टन ने कहा, किसी भी निष्पक्ष पर्यवेक्षक के लिए यह स्पष्ट है कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय अपने छात्रों को उत्पीड़न से बचाने में विफल रहा और वर्षों तक अपने परिसर में भेदभाव को पनपने दिया। हार्वर्ड का करदाताओं के पैसे पर संवैधानिक अधिकार नहीं है और वह भविष्य में अनुदान के लिए अयोग्य बना रहेगा। इस कठोर फैसले के खिलाफ अपील की जाएगी। हमें विश्वास है कि हार्वर्ड को जवाबदेह ठहराने में हम सफल होंगे।

हार्वर्ड विवि को ट्रंप प्रशासन के साथ टकराव में महत्वपूर्ण कानूनी जीत मिली

एजेंसी

वाशिंगटन (अमेरिका)। हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने ट्रंप प्रशासन के साथ टकराव में महत्वपूर्ण कानूनी जीत हासिल की। बोस्टन स्थित अमेरिकी जिला न्यायालय की न्यायाधीश एलिसन डी. बरोज ने कहा कि सरकार ने यहूदी-विरोधी भावना को जड़ से खत्म करने के नाम पर अरबों डॉलर के अनुसंधान कोष को रोककर कानून तोड़ा है। कानूनविद् कहते हैं कि यह फैसला हार्वर्ड को व्हाइट हाउस के साथ समझौता वार्ता में नई ताकत दे सकता है।

द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर में बोस्टन स्थित अमेरिकी जिला न्यायालय की न्यायाधीश एलिसन डी. बरोज के फैसले की जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया है कि यह एकमात्र विश्वविद्यालय है जिसने अपने शोध निधि पर प्रशासन के लक्षित हमले के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। न्यायाधीश बरोज ने 84 पृष्ठों के अपने फैसले में लिखा, हमें यहूदी-

विरोध के खिलाफ लड़ना होगा, लेकिन हमें अपने अधिकारों की भी रक्षा करनी होगी, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है और किसी भी लक्ष्य को दूसरे की वेदी पर बलिदान नहीं किया जाना चाहिए। चाहिए। उन्होंने कहा, हार्वर्ड वर्तमान में, भले ही देर से ही सही, यहूदी-विरोध से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है और जरूरत पड़ने पर और भी अधिक करने को तैयार है। न्यायाधीश एलिसन डी. बरोज ने कहा, अब अदालतों का काम है कि वे भी इसी तरह आगे आएं। संविधान द्वारा अपेक्षित शैक्षणिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कदम उठाएं। यह सुनिश्चित करें कि महत्वपूर्ण शोध को अनुचित रूप से मनमाने और प्रक्रियात्मक रूप से कमजोर अनुदानों से न रोका जाए, भले ही ऐसा करने से अपने एजेंडे के प्रति प्रतिबद्ध सरकार के क्रोध का जोखिम हो, चाहे इसके लिए उसे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। निर्णय के एक भाग के रूप में, न्यायाधीश बरोज ने कहा कि ट्रंप प्रशासन हार्वर्ड के संघीय अनुसंधान निधि पर 'अपने प्रथम संशोधन अधिकारों के प्रयोग के प्रतिशोध में या नागरिक अधिकार कानून की शर्तों के अनुपालन के बिना भेदभाव के किसी भी कथित आधार पर' नई रुकावटें जारी नहीं कर सकता।

किम जोंग उन की कुर्सी की सफाईः जाने के बाद स्टाफ ने क्यों रगड़-रगड़ कर धोया

एजेंसी

बीजिंग। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के सार्वजनिक कार्यक्रमों के बाद अजीबोगरीब प्रोटोकॉल का पालन करने का एक मामला सामने आया है। एक वीडियो में देखा गया कि जिस कुर्सी पर किम बैठे थे, उनके जाने के तुरंत बाद स्टाफ के सदस्य उसे रगड़-रगड़कर साफ करने लगे। यह घटना दुनियाभर में चर्चा का विषय बनी हुई है।

वजह है सुरक्षा और गोपनीयता

बताया जाता है कि इस अजीबोगरीब सफाई के पीछे किम जोंग उन की सुरक्षा और गोपनीयता की चिंता है। माना जाता है कि किम के शरीर से निकलने वाले किसी भी डीएनए या जैविक पदार्थ को मिटाने के लिए ऐसा किया जाता है, ताकि उनकी सेहत से जुड़ी कोई भी जानकारी लीक न हो सके। किम की निजी जिंदगी और स्वास्थ्य को लेकर उत्तर कोरिया बेहद सतर्क रहता है और इसे गोपनीय रखता है।

तैयारी और सुरक्षा की झलक

यह घटना दिखाती है कि किम जोंग उन की सुरक्षा व्यवस्था कितनी कड़ी है। उनके हर सार्वजनिक दौरे से पहले और बाद में कड़ी सुरक्षा जांच और प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है। स्टाफ द्वारा कुर्सी की सफाई करना भी इसी सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा है।

भारत के नए इमिग्रेशन नियमों से नेपाल और भूटान के नागरिकों को छूट

एजेंसी

काठमांडू। भारत सरकार ने 2 सितंबर से पूरे देश में जो नए आप्रवासन नियम लागू किए हैं उससे नेपाल और भूटान के नागरिकों को छूट दी गई है। नए नियम में किसी भी विदेशी नागरिक को भारत प्रवेश करने पर अनिवार्य रूप से फॉर्म सी भरने का निर्देश जारी किया गया है। भारत के गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि नए आप्रवासन नियमों से नेपाल और भूटान के नागरिकों को अलग रखा गया है। गृह मंत्रालय के इस नए नियम को लेकर नेपाल में संशय उत्पन्न होने के बाद काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने एक बयान जारी कर नेपाल और भूटान के नागरिकों को इस नए नियम से अलग रखने की जानकारी दी गई है। भारतीय दूतावास ने साफ किया है कि भारत के गृह मंत्रालय के तरफ से 2 सितंबर से लागू नए आप्रवासन नियमों से नेपाल और भूटान के नागरिकों को अलग रखा गया है। इस बयान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत के गृह मंत्रालय द्वारा जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक नेपाल और भूटान के नागरिकों को नेपाल में प्रवेश करते समय पासपोर्ट या वीजा की कोई अनिवार्यता नहीं है। नेपाल या भूटान के नागरिक अपने साथ गृह मंत्रालय द्वारा चिन्हित किसी भी परिचय पत्र के साथ भारत की यात्रा कर सकते हैं। इनमें पासपोर्ट या नागरिकता का प्रमाणपत्र या वोटर आईडी कार्ड में से कोई भी एक होने पर हवाई मार्ग या सड़क मार्ग से भारत में प्रवेश कर सकते हैं। इसके अलावा 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए उनके स्कूल द्वारा जारी फोटो परिचय पत्र को मान्यता दिया गया है। साथ ही विशेष परिस्थिति में नई दिल्ली स्थित नेपाली या भूटानी दूतावास और काठमांडू और थिंपू स्थित भारतीय दूतावास के द्वारा जारी प्रमाण पत्र एक बार के लिए मान्य होगा।

भारतीय दूतावास द्वारा जारी सूचना में यह भी कहा गया है कि नए आप्रवासन कानून के तहत विदेश नागरिकों को भारत में प्रवेश करने के साथ ही जो फॉर्म सी भरने की अनिवार्यता है उससे भी नेपाली और भूटानी नागरिकों को अलग रखा गया है। नेपाल और भूटान के नागरिकों के लिए किसी भी प्रकार का फॉर्म एयरपोर्ट या होटल में भरना आवश्यक नहीं है।

नाइजीरिया में नाव दुर्घटना में 60 लोगों की मौत

एजेंसी

अबुजा। नाइजीरिया के उत्तर-मध्य नाइजर राज्य में एक नाव के पलट जाने से कम से कम 60 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोगों को बचा लिया गया। स्थानीय अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

बोर्गु स्थानीय सरकारी क्षेत्र के अध्यक्ष अब्दुल्लाही बाबा आरा ने कहा, नाव दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 60 हो गई है और हताहतों की संख्या बढ़ रही है।÷ उन्होंने आगे बताया कि 10 लोगों की हालत गंभीर है और कई अन्य अभी भी लापता हैं। नाइजर राज्य आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी के अनुसार, आपातकालीन कर्मी और स्थानीय गोताखोर पीड़ितों की तलाश कर रहे हैं।यह दुर्घटना स्थानीय समयानुसार सुबह लगभग 11 बजे

हुई, जब बोर्गु स्थानीय सरकारी क्षेत्र में गौसावा समुदाय के पास एक अतिभारित नाव एक पेड़ के ठूंठ से टकराकर पलट गई। शगुमी के जिला प्रमुख सादु इनुवा मुहम्मद ने बताया कि नाव में 100 से ज़्यादा लोग सवार थे, जिनमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। नाइजीरिया में अक्सर नाव दुर्घटनाएँ, जो अक्सर क्षमता से अधिक सामान लादने, खराब मौसम और संचालन संबंधी त्रुटियों के कारण होती हैं, आम हैं।

अफगानिस्तान के तखर प्रांत में 78 किग्रा अफीम के साथ एक तस्कर गिरफ्तार

एजेंसी

काबुल। उत्तरी अफगानिस्तान के तखर प्रांत में पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 78 किलोग्राम अफीम बरामद किया है। प्रांतीय पुलिस प्रवक्ता निज़ामुद्दीन ओमीर ने यह जानकारी दी। पुलिस ने

कथित नशीले पदार्थों के तस्कर की कार की डिक्की से 78 किलोग्राम अफीम बरामद किया और वह मादक पदार्थ को तखर से किसी अज्ञात स्थान पर ले जा रहा था लेकिन पुलिस ने नियमित तलाशी के दौरान मादक पदार्थ बरामद कर उसे गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि पिछले तीन दिनों में अफ़ग़ानिस्तान के उत्तरी क्षेत्र में प्रतिबंधित मादक पदार्थों की यह दूसरी बरामदगी है। इससे पहले पुलिस ने मंगलवार को उत्तरी बगलान प्रांत में 18 किलोग्राम अफीम बरामद कर पुलिस ने दो तस्करों को हिरासत में लिया था।

पाकिस्तान में मूसलाधार बारिश से 883 लोगों की मौत, इस्लामाबाद में 'बाढ़' की चेतावनी

एजेंसी

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में जून के अंत से हो रही मूसलाधार बारिश से हर तरफ तबाही का मंजर है। इस मानसूनी बारिश में हुए हादसों में अब तक 883 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 1,200 घायल हुए हैं। स्थानीय मीडिया ने गुरुवार को बताया कि बुधवार देर रात से बारिश से जुड़ी घटनाओं में दो और बच्चों की जान चली गई। इनमें से एक की मौत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) और दूसरे की जान इस्लामाबाद में गई। पाकिस्तान मौसम विज्ञान विभाग (पीएमडी) ने चेतावनी दी है कि ऊपरी क्षेत्रों में जारी भारी बारिश लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में शहरी बाढ़ का कारण बन सकती है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने अपने राष्ट्रीय आपात संचालन केंद्र (एनईओसी) के माध्यम से अगले 12 से 24 घंटों में पाकिस्तान के कई क्षेत्रों में संभावित बारिश की चेतावनी जारी की थी। खैबर-पख्तूनख्वा (केपी) और पंजाब प्रांतों को बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। केपी में

488 लोगों की मौत हो गई है और 360 घायल हुए हैं। प्रमुख पाकिस्तानी दैनिक द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, सिंध में 58, पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित-बाल्टिस्तान (पीओजीबी) में 41, पीओके में 38, बलूचिस्तान में 26 और इस्लामाबाद में 9 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। पीएमडी ने चेतावनी दी है कि पंजाब के गंदा सिंह वाला क्षेत्र में सतलुज नदी में बाढ़ का स्तर असाधारण रूप से ऊंचा बना रहेगा, जबकि चिनाब नदी में एक नई बाढ़ पंजाब के मराला से नीचे की ओर पहुंच सकती है।

रिपोर्ट से पता चलता है कि पंजनद नदी (जहां चिनाब, रावी और सतलुज नदियां मिलती हैं) में 4 और 5 सितंबर के बीच जलस्तर बढ़ने की आशंका है, जिससे हजारों एकड़ कृषि भूमि और सैकड़ों गांवों को गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। सिंध प्रांत के गुड्डू में सिंधु नदी में भी 6 या 7 सितंबर तक बाढ़ खतरनाक स्तर तक पहुंचने की आशंका है। पीएमडी के अधिकारियों ने पंजाब, केपी, पीओजीबी और पीओके के लिए बारिश की चेतावनी जारी की है। चित्राल, दीर, स्वात, बुनेर और एबटाबाद सहित केपी के विभिन्न क्षेत्रों में छिटपुट बारिश की संभावना है। अधिकारियों ने निचले इलाकों में बाढ़ की भी चेतावनी दी है, साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में नदियों के उफान पर होने और भूस्खलन का खतरा भी है। पीडीएमए के अनुसार, चिनाब नदी से आई बाढ़ ने पंजाब के झांग में 261 गांवों और मुजफ्फरगढ़ में कम से कम 24 गांवों को जलमग्न कर दिया है। बाढ़ में पानी के प्रचंड बहाव ने 9,200 से ज्यादा घरों को भी नष्ट कर दिया है, जिनमें से 4,700 केपी में और 2,100 पीओके में हैं। 6,000 से ज्यादा मवेशी बह गए हैं। इस आपदा में पूरे पाकिस्तान में लगभग 240 पुलों और 670 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों को नुकसान पहुंचाया है।

भारत में प्राकृतिक आपदाएँ

भारत में सबसे आम प्राकृतिक आपदाएँ चक्रवात, सूखा, अचानक बाढ़, हिमस्खलन, भूस्खलन और बर्फीले तूफान हैं. इन आपदाओं का कारण मुख्य रूप से भारत की जटिल भू-जलवायु, भौगोलिक विशेषताएँ और मानव गतिविधियाँ हैं. पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों की गति भूकंप का कारण बनती है, जबकि वनों की कटाई और अति-विकास बाढ़ और भूस्खलन की तीव्रता को बढ़ाते हैं.

भारत में प्रमुख प्राकृतिक आपदाएँ और उनके कारण–

बाढ़–

कारण– अत्यधिक वर्षा, नदियों का उफान, हिम पिघलना, बांधों का टूटना और अत्यधिक वन-कटाई. –

सूखा–

कारण– मानसून की कमी, कम वर्षा और वर्षा की अनियमितता.

चक्रवात–

कारण– अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले तूफान.

भूकंप–

कारण– भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट के साथ टकराव और टेक्टोनिक प्लेटों में ऊर्जा का जमा होना.

भूस्खलन–

कारण– मूसलाधार बारिश, अत्यधिक वन-कटाई, पर्वतीय क्षेत्रों में निर्माण और कृषि प्रथाएँ.

हिमस्खलन–

कारण– पहाड़ी क्षेत्रों में अत्यधिक बर्फबारी.

धूल भरी आंधी और ओलावृष्टि

कारण– गर्म और शुष्क क्षेत्रों में हवा का दबाव और अचानक होने वाली तीव्र हवाएं.

अन्य संबंधित कारक–

जलवायु परिवर्तन–

ग्लोबल वार्मिंग और मौसम के पैटर्न में बदलाव भी आपदाओं के जोखिम को बढ़ाता है.

मानव-जनित कारक–

वनों की कटाई, प्रदूषण और अंधाधुंध शहरीकरण जैसी मानवीय गतिविधियाँ, प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावों को बढ़ाती हैं.

प्राकृतिक आपदाओं के प्रति भारत की संवेदनशीलता ने लगातार बड़े पैमाने पर आर्थिक और सामाजिक नुकसान पहुँचाया है। स्विस रे के 2023 के विश्लेषण के अनुसार, भारत को 2023 में 12 अरब डॉलर (1 लाख करोड़ से अधिक) का आर्थिक नुकसान हुआ, जो 10 वर्षों के औसत 8 अरब डॉलर (2013–2022) से अधिक है। चक्रवात बिपरजॉय और मिचांग जैसी प्रमुख आपदाएँ, साथ ही विनाशकारी बाढ़, मज़बूत आपदा प्रबंधन रणनीतियों की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं। चूँकि बाढ़ अकेले कुल वार्षिक आर्थिक नुकसान का 63% हिस्सा है, इसलिए बेहतर तैयारी, प्रतिक्रिया तंत्र और दीर्घकालिक शमन उपायों की तत्काल आवश्यकता है।

भारत की भौगोलिक विविधता इसे चक्रवात, बाढ़, भूकंप और सूखे सहित कई प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील बनाती है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के अनुसार, भारत का लगभग 58.6% भूभाग भूकंप, 12% बाढ़ और 8% चक्रवातों के प्रति संवेदनशील है। यह संवेदनशीलता, अनियोजित शहरीकरण, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन के साथ मिलकर, आपदाओं के पैमाने और प्रभाव को और बढ़ा देती है। इसके आर्थिक निहितार्थ भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अपर्याप्त तैयारी और शमन उपायों के कारण हर साल नुकसान बढ़ रहा है।

भारत में 2001 के गुजरात भूकंप और 2013 के उत्तराखंड बाढ़ जैसी विनाशकारी घटनाओं का इतिहास एक सुदृढ़ आपदा प्रबंधन ढाँचे की तत्काल आवश्यकता को उजागर करता है। जलवायु परिवर्तन के कारण आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता एक सक्रिय दृष्टिकोण के महत्व को और भी स्पष्ट करती है।

प्रमुख आपदाएँ और उनके प्रभाव (2023)

चक्रवात बिपरजॉय (16 जून, 2023)

अवलोकन – चक्रवात बिपरजॉय, एक गंभीर चक्रवाती तूफान, गुजरात के कच्छ जिले में पहुंचा, जिसके साथ 140 किमी/घंटा की गति से तेज हवाएं चलीं और भारी वर्षा हुई।

प्रभाव –

बुनियादी ढांचा – कांडला और मुंद्रा जैसे बंदरगाह बुरी तरह से बाधित हुए, जिससे व्यापार और रसद प्रभावित हुई।

कृषि – 50,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि नष्ट हो गई, विशेष रूप से कपास और मूंगफली की फसलें प्रभावित हुईं।

मानव विस्थापन – न्यूनतम हताहत सुनिश्चित करने के लिए 300,000 से अधिक लोगों को निचले इलाकों से निकाला गया।

आर्थिक नुकसान – 6,000 करोड़ से अधिक अनुमानित।

सर्वोत्तम अभ्यास – गुजरात की पूर्व-निवारक निकासी रणनीति और सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रमों ने मृत्यु दर को न्यूनतम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

चक्रवात मिचांग (5 दिसंबर, 2023)अवलोकन – चक्रवात मिचांग ने तमिलनाडु में अभूतपूर्व वर्षा की, जिससे विशेष रूप से चेन्नई प्रभावित हुआ।

शहरी बाढ़ – चेन्नई में 24 घंटे के भीतर 400 मिमी से अधिक वर्षा दर्ज की गई, जिससे जलभराव हो गया और दैनिक जीवन बाधित हो गया।

आर्थिक नुकसान – बुनियादी ढांचे की क्षति और व्यापार में रुकावट के कारण 4,500 करोड़ का नुकसान हुआ।

सार्वजनिक स्वास्थ्य – स्थिर पानी से जलजनित बीमारियों का खतरा बढ़ गया।

तुलना – भूमिगत जलाशयों और वर्षा जल संचयन सहित सिंगापुर की बाढ़ प्रबंधन प्रणालियां, शहरी नियोजन के लिए बहुमूल्य सबक प्रदान करती हैं।

उत्तरी भारत में बाढ़ (10–15 जुलाई, 2023)

अवलोकन – अभूतपूर्व मानसूनी बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में व्यापक बाढ़ आ गई।

प्रभाव –

हिमाचल प्रदेश – शिमला और कुल्लू में भूस्खलन और सड़कें अवरुद्ध होने से पर्यटन और कृषि प्रभावित हुई।

दिल्ली एनसीआर – यमुना नदी अपने तटों को तोड़ चुकी, जिससे प्रमुख क्षेत्र जलमग्न हो गए और हजारों लोग विस्थापित हो गए।

आर्थिक क्षति – कुल क्षति 10,000 करोड़ से अधिक हुई।

वैश्विक उदाहरण – नीदरलैंड की 卐नदी के लिए जगह卐 परियोजना दर्शाती है कि पानी के लिए अतिरिक्त स्थान बनाने से शहरी बाढ़ को कैसे रोका जा सकता है।

औद्योगिक और शहरी भेद्यतासकल घरेलू उत्पाद में राज्यवार योगदान

भारत के औद्योगिक राज्य अपने आर्थिक महत्व और बुनियादी ढांचे के संकेन्द्रण के कारण प्राकृतिक आपदाओं के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हैं–

गुजरात – भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 13.3% का योगदान देने वाला यह राज्य चक्रवातों और भूकंपों के खतरों का सामना करता है।

महाराष्ट्र – सकल घरेलू उत्पाद में 13卐 हिस्सेदारी के साथ, मुंबई में शहरी बाढ़ एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय बनी हुई है।

तमिलनाडु – सकल घरेलू उत्पाद में 10.5% योगदान देने वाले चक्रवात और बाढ़ अक्सर चेन्नई की अर्थव्यवस्था को बाधित करते हैं।

शहरी केंद्र खतरे में

अहमदाबाद – भूकंप और गर्म लहरों से प्रभावित।

मुंबई – खराब जल निकासी प्रणालियों के कारण हर साल मानसून में बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है।

चेन्नई – चक्रवातों और शहरी बाढ़ से नियमित रूप से प्रभावित।

दिल्ली एनसीआर – यमुना नदी से आने वाली बाढ़ और भूकंपीय खतरों के प्रति संवेदनशील।

भारत में आपदा प्रबंधन कानूनी ढांचा

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 –

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) की स्थापना की गई।

राज्य एवं जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को सशक्त बनाता है।

संस्थागत व्यवस्थाएनडीएमए – आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां, दिशानिर्देश और योजनाएं तैयार करता है।

एस.डी.एम.ए. – राज्य स्तर पर नीतियों का कार्यान्वयन।

डीडीएमए – जिला-विशिष्ट आपदा प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना।

प्रमुख नीतियां

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम), 2009 –

तैयारी, प्रतिक्रिया, पुनर्प्राप्ति और शमन को कवर करने वाले एक समग्र दृष्टिकोण की वकालत करता है।

सामुदायिक भागीदारी और क्षमता निर्माण पर जोर दिया गया।

आपदा प्रबंधन में चुनौतियाँ

बुनियादी ढांचे की कमी –

चक्रवात और बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में लचीली संरचनाओं की संख्या सीमित है। शहरी क्षेत्रों में जल निकासी प्रणालियों का खराब रखरखाव।

भूकंप-प्रवण क्षेत्रों में रेट्रोफिटिंग का अभाव।

समन्वय अंतराल –केंद्रीय, राज्य और स्थानीय निकायों के बीच अप्रभावी संचार।

आपातकाल के दौरान संसाधन आवंटन में देरी। आपदा जोखिमों के बारे में समुदाय की जागरूकता सीमित है। तेजी से शहरीकरण और वनों की कटाई से जोखिम बढ़ जाता है। समुद्र के बढ़ते स्तर के कारण तटीय आबादी को भारी खतरे का सामना करना पड़ रहा है आपदा से संबंधित 90% से अधिक नुकसान बीमाकृत नहीं होते । दीर्घकालिक शमन परियोजनाओं के लिए धन का अपर्याप्त आवंटन।आपदा प्रबंधन में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाएँ

जापान – उन्नत भूकंप-रोधी भवन संहिता और सामुदायिक अभ्यास।

Source:support@upscguide.in; (compiled by: C M Sharma)

सीटीएम प्रबंधन ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत सामग्री की गाड़ी रवाना की

कठुआ, 04 सितंबर (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर के जिला कठुआ में स्थित सबसे बड़ी इकाई चिनाब टेक्सटाइल मिल्स ने हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए राहत सामग्री वितरण अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत सक्षम संस्था के सहयोग से आपदा प्रभावित क्षेत्रों को चिन्हित किया जा रहा है और प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री वितरित की जा रही है।

गुरुवार को कठुआ के दयालचक के समीप जसरोटा विधानसभा क्षेत्र के अधीन पड़ते गांव परंगोली में चिनाब टेक्सटाइल मिल्स प्रबंधन से कार्यकारी अध्यक्ष यू के पटनायक, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोज कुमार झा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आर के बंसल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी के लोढ़ा ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री की गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अभियान के तहत 100 से अधिक प्रभावित परिवारों को खाने-पीने का सामान वितरित करने के लिए राहत सामग्री से भरी गाड़ी को रवाना किया गया। सीटीएम प्रबंधन से यू के पटनायक, मनोज कुमार ने बताया कि इस वर्ष जम्मू-कश्मीर में बहुत बड़ी आपदा आई है, जिसमें कई लोगों के घरों को क्षति पहुंची है, खाने-पीने से भी वंचित हो चुके हैं। वहीं सीटीएम प्रबंधन ने मानवता के आधार पर प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत प्रदान करने का बीड़ा उठाया है। इसके लिए सक्षम संस्था के सहयोग से आपदा प्रभावित क्षेत्रों को चिन्हित किया जा रहा है और प्रभावित परिवारों की सूची तैयार की जा रही है। जिसके बाद प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री वितरित की जा रही है, जिसमें खाने-पीने की सामग्री शामिल है। सीटीएम प्रबंधन ने कहा कि राहत सामग्री वितरण का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा और अन्य प्रभावित क्षेत्रों में भी राहत सामग्री पहुंचाई जाएगी। सीटीएम प्रबंधन ने आमजन से भी अपील की है कि जो लोग सक्षम हैं और दूसरे की मदद कर सकते हैं, उन्हें इस मुश्किल घड़ी में सामने आकर आपदा प्रभावित लोगों की मदद करनी चाहिए। यह एक अच्छा कदम है और इससे प्रभावित परिवारों को काफी राहत मिलेगी

डीजीबीआर ने जम्मू संभाग में सड़क बुनियादी ढांचे का निरीक्षण किया

जम्मू, 4 सितंबर (हि.स.)। लेफ्टिनेंट जनरल रघु निवासन, पीवीएसएम, डीजीबीआर ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में हाल ही में हुई अभूतपूर्व बारिश से प्रभावित सड़कों का निरीक्षण किया। उन्होंने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण दो सड़कों रामकोट-रणजीत सागर बांध और बशोली-बनी रोड का दौरा किया। इन दोनों सड़कों को व्यापक क्षति पहुंची है. उन्होंने पेडू नाला स्थान का दौरा किया जहां भारी भूस्खलन के कारण दो पुल विस्थापित हो गए थे।

उन्होंने यातायात बहाल करने के लिए बनाये जा रहे डायवर्सन के निर्माण का निरीक्षण किया। उन्होंने बनी बशोली रोड पर किमी 47 पर भूंड का दौरा किया जहां सड़क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बाढ़ में पूरी तरह से बह गया था जिससे सड़क में जगह बन गई है।

उन्होंने सड़क संचार को बहाल करने के लिए पूरी तरह से नए पहुंच संरेखण के निर्माण में फॉर्मेशन कटिंग कार्य का निरीक्षण किया। अपनी यात्रा के दौरान, डीजीबीआर ने बशोली के विधायक दर्शन कुमार से बातचीत की और उन्हें जल्द से जल्द सड़क संचार बहाल करने के लिए बीआरओ द्वारा प्रयासों

का आश्वासन दिया। डीजीबीआर ने सड़क संचार बहाल करने के प्रयासों के लिए प्रोजेक्ट संपर्क के कर्मियों की सराहना की। उन्होंने सभी कर्मियों को आने वाले दिनों में भी अच्छा काम जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया।